केंद्र की मोदी सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 3 फीसदी बढ़ाया गया है। साथ ही महंगाई राहत में भी 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।

जनहितैषी

हिन्दी दैनिक

R.N.I. No. 63177/95 वर्ष:27 अंक: 106 दिनांक: 31-03-2022 गुरूवार मूल्य : 100 पैसा पृष्ठ:4 अहमदाबाद M

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हाइड्रोजन से चलने वाली कार से आज संसद भवन पहुंचे। इस हाइड्रोजन से चलने वाली कार को कथित तौर पर एक बार टैंक फुल करने के बाद 600 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है।

मोदी सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, डीए में 3 फीसदी इजाफा

नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्र की मोदी सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 3 फीसदी बढ़ाया गया है। साथ ही महंगाई राहत में भी 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 34 फीसदी हो गया है, जबकि महंगाई राहत भी बढ़कर 34 फीसदी पर आ गई है। ये फैसला 1 जनवरी 2022 से प्रभावी है।

महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दोनों के कारण सरकारी खजाने पर कुल 9,544.50 करोड़ रुपये प्रति वर्ष बोझ बढ़ेगा। मोदी सरकार के नए फैसले से लगभग 47.68 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। बता दें कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक साल में दो बार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की जाती है। ये बढ़ोतरी छमाही आधार पर की जाती है। इस बार की बढ़ोतरी 1 जनवरी से 30 जनू तक के लिए लागू होगी।

इस बढ़ोतरी के बाद डीए बढ़कर 31 फीसदी हो जाएगा। अभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 31 प्रतिशत के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। लेकिन सरकार इसे 3 प्रतिशत बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों को अप्रैल के वेतन के साथ में नए महंगाई भत्ते का पूरा पेमेंट किया जाएगा। अप्रैल के महीने में कर्मचारियों को उनका पिछले 3 महीने का सारा एरियर भी दिया जाएगा। 3 फीसदी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को 73,440 से लेकर 2,32,152 20 रुपये तक के एरियर का लाभ मिलेगा। एक अनुमान के मुताबिक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के खजाने पर प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रुपये का बोझ आएगा। इस कदम से 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। दरअसल माना जा रहा ता होली के पहले ही सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान करेगी लेकिन ये फैसला अब लिया गया है।

पांचवें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी

नई दिल्ली (ईएमएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांचवें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए और उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। वर्चुअल मोड में आयोजित होने वाले डमिट की मेजबानी वर्तमान बिम्सटेक अध्यक्ष श्रीलंका द्वारा की गई। इस दौरान पीएम मोदी ने दुनिया के समक्ष जो संकट है उस पर बात की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा यूरोप में हाल के घटनाक्रमों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में क्षेत्रीय सहयोग करना एक बड़ी प्राथमिकता बन गई है। आज हम अपने समूह के लिए संस्थान की संरचना विकसित करने के लिए बिम्सटेक चार्टर अपना रहे हैं। 5वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि हम नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित बिम्सटेक छात्रवृत्ति कार्यक्रम के दायरे का विस्तार और विस्तार करने पर काम कर रहे हैं। हम आपराधिक मामलों पर आपसी कानूनी सहायता पर एक संधि पर भी हस्ताक्षर कर रहे हैं।

बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी बोले कि बंगाल की खाड़ी को संपर्क, समृद्धि और सुरक्षा का पुल बनाने का समय आ गया है। मैं सभी बिम्सटेक देशों का आह्वान करता हूं कि वे 1997 में एक साथ हासिल किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नए उत्साह के साथ काम करने के लिए खुद को समर्पित करें। भारत अपने परिचालन बजट को बढ़ाने के लिए (बिम्सटेक) सचिवालय को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा, (बिम्सटेक) सचिवालय की क्षमता को मजबूत करना महत्वपूर्ण है, मेरा सुझाव है कि महासचिव इसके लिए एक रोडमैप तैयार करें।

मान का शिक्षा पर बड़ा फैसला, निजी स्कूलों की फीस बढ़ाने पर पाबंदी

चंडीगढ़ (ईएमएस)। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने शिक्षा के क्षेत्र में दो बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने निजी स्कूलों के फीस बढ़ाने पर पाबंदी लगा दी है। इसके बाद स्कूलों में होने वाले एडमिशन में फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही दूसरा बड़ा फैसला हैं, कि कोई भी स्कूल किसी खास दुकान से बुक और ड्रेस खरीदने के लिए नहीं बोल सकता हैं। माता-पिता बच्चे के लिए अपनी सहूलियत के हिसाब से किताब-ड्रेस किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने निजी स्कूलों को स्कूल फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी है। पंजाब सरकार एक नीति लेकर आएगी, नीति को माता-पिता की सहमति से तैयार किया जाएगा। निजी स्कूलों को भी अनुशंसित किताब की दुकान से माता-पिता को किताबें और अन्य सामान खरीदने के लिए मजबूर करने की अनुमति नहीं होगी। अभिभावक अपनी पसंद की दुकानों से पाठय पुस्तकें व अन्य स्टेशनरी सामग्री खरीदने के लिए स्वतंत्र होगा। इसके पहले पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने पंजाब में भी राशन की डोर टू डोर राशन डिलीवरी का ऐलान किया था। यानी अब सरकार घर घर में राशन की डिलीवरी होगी।

बता दें कि सत्ता संभालने के बाद से मान एक के बाद कर बड़े फैसले कर रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार को मान ने विधायकों की पेंशन में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया था। मान के मुताबिक, अब से विधायकों को एक बार पेंशन मिलेगी। अब तक जितनी बार कोई विधायक बनता था, पेंशन की राशि जुड़ती जाती थी। इतना ही नहीं मान ने विधायक के परिवार को मिलने वाली पेंशन में भी कटौती करने का ऐलान किया था।

रद्द हो सकती है लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष की जमानत

-सुप्रीम कोर्ट ने कहा- लखीमपुर खीरी कांड की निगरानी समिति ने की सिफारिश

नई दिल्ली(ईएमएस)। यूपी के चर्चित लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यूपी सरकार को बताया कि लखीमपुर हिंसा मामले की जांच की निगरानी कर रहे न्यायाधीश ने आशीष मिश्रा को दी गई जमानत को रद्द करने की सिफारिश की है। साथ ही इस मामले में जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ ने यूपी सरकार के वकील से सवाल किया, 'निगरानी न्यायाधीश की रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि उन्होंने जमानत रद्द करने की सिफारिश की थी। आपका क्या रुख है?'

पीठ ने कहा कि एसआईटी के पास अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश को दो लिखित पत्र थे। उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा कि उन्हें पत्रों के बारे में कोई जानकारी नहीं है और उन्होंने मामले में निर्देश लेने के लिए कुछ समय मांगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि निगरानी न्यायाधीश ने सिफारिश की है कि मिश्रा को दी गई जमानत को चुनौती दी जानी चाहिए। जेठमलानी ने मामले में जवाब देने के लिए पांच मिनट का समय मांगा। पीड़ित परिवारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि शीर्ष अदालत को या तो उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगानी चाहिए या मिश्रा को दी गई जमानत रद्द करनी चाहिए। दवे ने कहा, ठउच्च न्यायालय का आदेश पूरी तरह से सही नहीं हैठ

जेठमलानी ने कहा कि उन्होंने अतिरिक्त गृह सचिव से बात की है और उन्हें जांच की निगरानी कर रहे न्यायाधीश से पत्र नहीं मिले हैं। पीठ ने कहा कि न्यायाधीश के पत्रों की प्रति राज्य सरकार को दी जानी चाहिए। जेठमलानी ने पीठ से मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को रखने का अनुरोध किया। पीठ ने जवाब दिया कि एक महीने से ज्यादा हो गया है और अब इस मामले को नहीं उठाया जा सकता है। सुनवाई की अगली तारीख 4 अप्रैल रखी गई है। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा जांच की निगरानी के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया था।

पीएम मोदी की अध्यक्षता में 15 हल्के लड़ाकू हेलीकाप्टरों की खरीद को मंजूरी

नई दिल्ली (ईएमएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार को 15 हल्के लड़ाकू हेलीकाप्टरों की लिमिटेड सीरिज प्रोडक्शन के तहत खरीद को मंजूरी दी। इस पर 3,887 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। इन हेलीकाप्टरों के रखरखाव के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर 377 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि लाइट काम्बैट हेलीकाप्टर लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन (एलएसपी) एक स्वदेशी अत्याधुनिक आधुनिक लड़ाकू हेलीकाप्टर है। इसमें 45 फीसद स्वदेशी साजो-सामानों का इस्तेमाल किया गया है। लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन (एलएसपी) वर्जन में बढ़कर 55 फीसद से ज्यादा हो जाएगी। यह दुनिया का सबसे हल्का अटैक हेलिकाप्टर है। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने इसे वर्षों की मेहनत के बाद विकसित किया है।

रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड यानी बीईएल की बेंगलुरु और हैदराबाद इकाइयों के साथ भी दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। 3,102 करोड़ रुपये के इन समझौतों से भारतीय वायु सेना के विमान की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। रक्षा मंत्रालय और बीईएल बेंगलुरु के बीच हुए करार के तहत भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमानों के लिए उन्नत इलेक्ट्रानिक युद्धक सूट की आपूर्ति के लिए समझौते पर दस्तखत किए हैं।

धरती और आकाश को समझने में मदद करता है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। प्रतीकात्मक

अंतरिक्ष तक रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जंग की आंच, आइएसएस पर क्यों मंडरा रहा खतरा?

कश्मीर में महिला ने सीआरपीएफ के बंकर पर फेंका पेट्रोल

जम्मू (ईएमएस)। जम्मू-कश्मीरके सोपोर जिले का एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हिजाब पहने हुए एक महिला सीआरपीएफ के बंकर पर पेट्रोल बम फेंकती दिख रही है। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें महिला बैग से पेट्रोल बम निकालकर फेंकती नजर आ रही है। वीडियो में बंकर में लगी आग को बाद में सीआरपीएफ के जवाब बुझाते नजर आते हैं। इस घटना से आतंकी गतिविधियों में महिलाओं के भी शामिल होने के सबूत मिलने की बात सामने आई है।

यूपी में इंटरमीडिएट का अंग्रेजी का पेपर लीक, 275 केंद्रों पर परीक्षा निरस्त

-यूपी एसटीएफ को सौंपी जांच, अब अगली डेट पर देनी होगी परीक्षार्थियों को परीक्षा

-भाजपा सरकार की दूसरी पारी में भी पेपर लीक कराने का व्यवसाय जारी:अखिलेश यादव

नई दिल्ली(ईएमएस)। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट का इंग्लिश का पेपर लीक होने के चलते 275 एग्जाम सेंटरों पर परीक्षा निरस्त कर दी गई है। आज़मगढ़ बलिया जिले में इंग्लिश का पेपर लीक होने पर आज़मगढ़ के सभी सेंटरों पर परीक्षा निरस्त कर दी गई है। परीक्षार्थियों को अगली डेट पर परीक्षा देनी होगी। मामले की जांच यूपी एसटीएफ को सौंप दी गई है और सभी 24 जिलों के डीएम-एसपी से भी रिपोर्ट मांगी गई है। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दे दी गई है। बागपत जनपद समेत 23 अन्य जनपदों मे दोपहर की पाली मे होने वाली इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। डीएम राजकमल यादव ने इसकी जानकारी दी है। जिलाधिकारी के आदेशानुसार 30 मार्च को इंटरमीडिएट दूसरी पाली की अंग्रेजी की परीक्षा सभी परीक्षा केंद्रों पर निरस्त कर दी गई है। जारी नोटिस के अनुसार, 30 मार्च की दूसरी शिफ्ट की अंग्रेजी की परीक्षा के पर्चे लीक होने के संभावना के चलते एग्जाम रद्द कर दिया गया है।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पेपर लीक मामले में सरकार की जमकर आलोचना की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यूपी की भाजपा सरकार की दूसरी पारी में भी पेपर लीक करवाने का व्यवसाय बदस्तूर जारी है। युवा कह रहे हैं कि रोजगार देने में नाकाम पर भाजपा सरकार जान-बूझकर किसी परीक्षा को पूर्ण नहीं होने देना चाहती है। भाजपा सरकार अपने इन पेपर माफियाओं पर दिखाने के लिए ही सही कागज का बुलडोजर चलवा दें।

इन जिलों में रद्द हुई परीक्षा: आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, बदायूं, शाहजहांपुर, उन्नाव, सीतापुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, अम्बेडकरनगर, प्रतापगढ़, गोंडा, गोरखपुरी, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, कानपुर देहात, एटा, और शामली। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू हुई हैं। आज 30 मार्च को दूसरी शिफ्ट में इंटरमीडिएट का अंग्रेजी का पेपर होना था। परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया जिसके चलते लाखों छात्र प्रभावित हुए हैं। एग्जाम की नई डेट अब जल्द जारी की जाएगी।

पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाना और सरकारी कंपनियों को 'बेचना पीएम का रोज का काम : राहुल

नई दिल्ली (ईएमएस)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई एवं बेरोजगारी के मुद्दों पर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाना, सरकारी कंपनियों को 'बेचना' और किसानों को 'लाचार करना' उनका रोजमर्रा का काम हो गया है। उन्होंने ट्वीट किया, ''प्रधानमंत्री की डेली टू डू लिस्ट (रोज करने वाले कामों की सूची): पेट्रोल-डीजल-गैस का रेट कितना बढ़ाऊं, लोगों की 'खर्चे पे चर्चा' कैसे रुकवाऊं, युवाओं को रोजगार के खोखले सपने कैसे दिखाऊं, आज किस सरकारी कंपनी को बेचूं, किसानों को और लाचार कैसे करूं।

गौरतलब है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बुधवार को फिर 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। पिछले नौ दिनों में कुल 5.60 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियों की तरफ से जारी मूल्य संबंधी अधिसूचना के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100.21 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर अब 101.01 रुपये प्रति लीटर और डीज़ल की कीमत 91.47 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 92.27 रुपये प्रति लीटर हो गई है।

योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के लिए पहुंचे शिवपाल यादव, बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज

लखनऊ । प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (प्रसपा) के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात करने पहुंचे। इस मुलाकात के बाद से सियासी गलियारे में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। हालांकि, शिवपाल सिंह यादव के खेमे ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया है।

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के रवैये से आहत सपा विधायक व प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (प्रसपा) के मुखिया शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का हाथ थाम सकते हैं। शिवपाल, अखिलेश की उपेक्षा से नाराज चल रहे हैं।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बुलाई गई सहयोगी दलों की बैठक में शामिल न होकर पिछले दिनों दिल्ली गए शिवपाल की भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की चर्चाओं के बीच वह बुधवार को लखनऊ लौटे। यहां उन्होंने देर शाम सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। चर्चा यह भी है कि भाजपा उन्हें राज्यसभा भेज सकती है।

सतह से हवा में मार करने वाली दो और मिसाइलों का परीक्षण सफल

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारत ने बुधवार को ओडिशा तट से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली दो और मिसाइलों का परीक्षण किया। डीआरडीओ के सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोपहर से पहले चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज लॉन्च पैड-3 से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों (एमआरएसएएम) का परीक्षण किया गया।

सूत्रों ने कहा कि दोनों परीक्षण सफल रहे हैं। रविवार को भी आईटीआर से सेना के दो एमआरएसएएम का परीक्षण किया गया था। बालासोर के जिला प्रशासन ने परीक्षण से पहले, आस-पास रहने वाले लोगों को एक शिविर में स्थानांतरित कर दिया था। इससे दो दिन पहले ही बीते रविवार को डीआरडीओ ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा प्रणाली का दो बार सफल परीक्षण किया। ओडिशा के समेकित परीक्षण रेंज, चांदीपुर से हाई स्पीड वाले निशानों को भेदकर वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया।

पाकिस्तान में चरम पर सियासी संग्राम, अल्पमत में आई इमरान सरकार, अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली में चर्चा कल

इस्लामाबाद । पाकिस्तान की गठबंधन सरकार में शामिल एक अहम दल मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट-पाकिस्तान (एमक्यूएम-पी) ने बुधवार को विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में मतदान का एलान कर दिया। इसके साथ ही इमरान सरकार संसद में अल्पमत में आ गई है। सरकार में शामिल एमक्यूएम-पी कोटे के दो मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने आनन-फानन में कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाई। इस्तीफे की अटकलों के बीच गृह मंत्री राशिद खान ने दावा किया है कि इमरान 'आखिरी बाल तक खेलेंगे।

एमक्यूएम-पी प्रमुख खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा, 'हम सहिष्णुता व सच्चे लोकतंत्र की राजनीति के लिए नई शुरुआत करना चाहते हैं।' पार्टी ने गत दिवस सरकार के सामने तीन मांगें रखी थीं। संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली में एमक्यूएम-पी के सात सदस्य हैं। पांच सदस्यों वाली बलूचिस्तान अवामी पार्टी (बीएपी) सोमवार को विपक्ष के साथ जाने का एलान कर चुकी है। पाकिस्तान में सियासी खींचतान चरम पर पहुंच गई है। मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट-पाकिस्तान (एमक्यूएम-पी) के अलग होने से इमरान खान की सरकार अल्पमत में आती नजर आ रही है। अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली में चर्चा बुधवार को होनी है।

जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम फजल (जेयूआइ-एफ) के मुखिया मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया कि विपक्ष को 175 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। यह भी घोषणा की गई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष शहबाज शरीफ देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। शहबाज ने कहा कि यह बहुत अहम दिन है, क्योंकि विपक्ष की सभी पार्टियां पाकिस्तान की समस्याओं का सामना करने के लिए एकजुट हो चुकी हैं। उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री को इस्तीफा देते हुए नई परंपरा कायम करनी चाहिए।' पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि एमक्यूएम के विपक्षी दलों के साथ आने के बाद प्रधानमंत्री के पास इस्तीफे के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने भी दावा किया कि शहबाज जल्द ही देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे।

उधर, कैबिनेट की विशेष बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान राशिद ने कहा, 'इमरान ने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ धमकी वाला पत्र साझा किया। सहयोगियों ने इमरान के प्रति विश्वास जताया है।' इमरान ने रविवार की रैली में एक पत्र लहराते हुए दावा किया था कि विदेशी ताकतें पाकिस्तान सरकार को गिराने का प्रयास कर रही हैं। राशिद ने कहा कि इमरान विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के साथ संसद को धमकी वाले पत्र के बारे में जानकारी दे सकते हैं। एएनआइ के अनुसार, इमरान ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) पार्टी के सांसदों को अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अनुपस्थित रहने का निर्देश दिया है। सांसदों को मंगलवार को भेजे गए पत्र में उन्होंने कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को गिराने के लिए इमरान को 342 सदस्यीय निचले सदन में 172 मतों की जरूरत होगी। पीटीआइ ने अपने 155 व गठबंधन के सहयोगी दलों के 23 सांसदों के समर्थन से सरकार बनाई थी। दो घटक दल विपक्षी पाले में जा चुके हैं, जबकि पीटीआइ के दो दर्जन सांसदों ने भी बगावत कर दी है। अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाले इमरान पाकिस्तान के तीसरे प्रधानमंत्री हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की

नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। केजरीवाल द्वारा फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' पर दिए बयान के विरोध में बुधवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से प्रदर्शन किया गया था, इसी दौरान तोड़फोड़ की यह घटना सामने आई। सुबह 11:30 बजे धरना शुरू हुआ। 150 से 200 कार्यकर्ता, केजरीवाल निवास के बाहर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे थे। दोपहर 1 बजे के करीब कुछ कर प्रदर्शनकारी दो बैरिकेडिंग को तोड़कर मुख्यमंत्री निवास तक पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों के हाथ में पेंट का डब्बा भी था। मुख्यमंत्री आवास के गेट पर पेंट डाला गया, बूम बैरियर और ण्णऊ्र कैमरा टूटा पाया गया। मामले में पुलिस ने 70 लोगों को हिरासत में लिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि पंजाब में आप की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी, अरविंद केजरीवाल को मारना चाहती है। आज पुलिस की मौजूदगी में भाजपा के गुंडे, सीएम के घर पर पहुंच गए।

सिसोदिया ने कहा कि प्रदर्शनकारी, जानबूझकर पुलिस लेकर गए। वे लोग खतरनाक खेल खेल रहे हैं। पॉलिटिक्स तो बहाना है, ये तो सीधे-सीधे क्रिमिनल मामला है। किसी भी सीएम के घर तक क्या गुंडे ऐसे पहुंच सकते हैं?

आप सांसद संजय सिंह ने घटना के बाद लिखा, 'लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के निवास पर भाजपाई गुंडे हमला कर देते है और दिल्ली पुलिस उन्हें रोकने की जगह उनके साथ खड़ी दिखती है। भाजपाइयों याद रखना सबका हिसाब लिया जाएगाये लोकतंत्र है यहां जनता वक़्त आने पर तुम्हे वोट की लाठी से पीटेगी।'

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पुलिस की मौजूदगी में ''हमला'' कायराना कृत्य है जो दिखाता है कि आम आदमी पार्टी और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक से बीजेपी भयभीत है। उधर, भाजयुमो के राष्ट्रीय सचिव तेजिंदर पाल सिंह बग्गा किसी तरह की तोड़फोड़ से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के घर के निकट प्रदर्शन किया, लेकिन किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं की।

तमिल राष्ट्रवाद के जरिए अशांति फैलाने की साजिश, तमिलनाडु में लिट्टे को खड़ा करने के लिए की जा रही फंडिंग

-राष्ट्रीय जांच एजेंसी की चार्जशीट में बड़ा खुलासा

नई दिल्ली (ईएमएस)। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) के लिए फंडिंग जांच के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने छह लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। लिट्टे से जुड़े मामलों की जांच जोर पकड़ रही है और इंटेलिजेंस ब्यूरो भी इसको लेकर अलर्ट है। रिपोर्टों के अनुसार समूह को पुनर्जीवित करने के लिए पैसे निकालने के प्रयास किए जा रहे थे। हालांकि, इस बार इसका उद्देश्य उससे विभिन्न हैं, जिसके लिए श्रीलंका आधारित लिट्टे संगठन की स्थापना की गई थी।

इस बार ये कोशिशें तमिलनाडु को अशांत करके भारत में 'तमिल राष्ट्रवाद' को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। एनआईए ने 29 मार्च की एक प्रेस विज्ञप्ति में मामले की जानकारी दी है। एनआईए ने एक ट्वीट किया, एनआईए ने लिट्टे टेरर फंडिंग केस (आरसी-02/2022/एनआईए/डीएलआई) में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। विज्ञप्ति के अनुसार, मामला चेन्नई में 'क्यू' शाखा सीआईडी द्वारा प्राथमिकी संख्या 1/2021 के रूप में दर्ज किया गया और 18 जनवरी 2022 को एनआईए ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था। यह लिट्टे को फिर से जीवित करने की एक आपराधिक साजिश से संबंधित है।

इसके लिए जाली दस्तावेजों का सहारा लेकर खाते में पैसे जमा किए गए, ताकि गैरकानूनी और आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। एनआईए के अनुसार जांच में पता चला है कि लेचुमानन मैरी फ्रांसिस्का, टी केनिस्टन फर्नांडो और के भास्करन ने विदेशी संस्थाओं के साथ मिलकर निष्क्रिय बैंक खातों में जमा राशि को अवैध रूप से प्राप्त भारतीय पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके और फर्जीवाड़ा करने की साजिश रची।

गौरतलब है कि श्रीलंकाई नागरिक लेचुमानन मैरी फ्रांसिस्का (50) को चेन्नई हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किए जाने के बाद यह मामला सामने आया था। महिला इसी साल दिसंबर में एक साल के टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी। वह कोविड-19 महामारी के कारण भारत में रुकी। उसके बाद उन्होंने अन्ना नगर की शक्ति कॉलोनी में एक संपत्ति किराए पर ली। उसके बाद उसने एक किराये का समझौता प्राप्त किया और अपने नाम पर एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपनी राष्ट्रीयता को छुपाया। उसने एलपीजी कनेक्शन के माध्यम से एक भारतीय पासपोर्ट और एक मतदाता पहचान पत्र प्राप्त किया। पुलिस के अनुसार, उसके पास जाली भारतीय पासपोर्ट होने के कारण गिरफ्तारी की गई थी।

हिजाब पहनने की नहीं मिली परमिशन, 40 छात्राओं ने छोड़ा एग्जाम 7 परीक्षक भी निलंबित

बेंगलुरु (ईएमएस)। कर्नाटक के उडुपी जिले की 40 मुस्लिम छात्राओं ने पहली प्री-यूनिवर्सिटी परीक्षा छोड़ दी। छात्राओं का कहना था कि हिजाब विवाद को लेकर हाल में आए उच्च न्यायालय के उस आदेश से आहत हैं, जिसमें स्कूल में हिजाब पहनकर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। सूत्रों ने बताया कि छात्राएं 15 मार्च के अदालत के आदेश से आहत थीं, इसकारण उन्होंने हिजाब के बिना परीक्षा में नहीं उपस्थित होने का निर्णय लिया। मंगलवार को परीक्षा छोड़ने वाली छात्राओं में कुंडापुर की 24 लड़कियां, बिंदूर की 14 और उडुपी सरकारी कन्या पीयू कॉलेज की दो लड़कियां शामिल हैं।

यह छात्राएं कक्षा में हिजाब पहनने पर कानूनी लड़ाई में शामिल थीं। इन लड़कियों ने इससे पहले प्रैक्टिकल एग्जाम भी छोड़ दिए थे। आरएन शेट्टी पीयू कॉलेज में 28 मुस्लिम छात्राओं में से 13 परीक्षा में उपस्थित हुईं। हालांकि कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर परीक्षा केंद्र पहुंची, लेकिन उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली। उडुपी के भंडारकर कॉलेज की पांच में से चार छात्राओं ने परीक्षा दी और बसरूर शारदा कॉलेज की सभी छात्राएं परीक्षा में उपस्थित रहीं। नवुंदा सरकारी पीयू कॉलेज की आठ में से छह छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दी जबकि 10 मुस्लिम लड़कियों में से केवल दो परीक्षा में उपस्थित हुईं।

सूत्रों ने बताया कि जिले के कुछ निजी कॉलेजों ने लड़कियों को हिजाब पहनकर परीक्षा देने की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई करने से 24 मार्च को इनकार कर दिया था। इस बीच बुधवार को 7 परीक्षकों को भी निलंबित कर दिया गया, जिन्होंने छात्राओं को क्लास के अंदर हिजाब पहनने की परमिशन की दी थी। कर्नाटक के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा, 'मुझे जितनी जानकारी मिली है, उसके मुताबिक 7 परीक्षकों को निलंबित किया गया है। इन लोगों को हाई कोर्ट के आदेश का पालन न करने के चलते निलंबित कर दिया गया और उन्हें ड्यूटी पर वापस नहीं लिया गया।'

कार्टून कोना

पाठकों से निवेदन

प्रिय पाठक आपका प्रिय समाचार पत्र जनहितैषी पिछले कई वर्षों से मात्र १रू. के मूल्य पर दिया जा रहा है। किन्तु अब अखबारी कागज, इन्क के दामों में वृद्धि व अन्य खर्चों में बढ़ो

जन हितैषी

पुतिन के तेवर

रूस और यूक्रेन के बीच जंग को एक माह से ज्यादा का समय हो गया है। दूसरी तरफ इस संकट का डिप्लोमैटिक समाधान भी तलाशा जा रहा है। इसी के मद्देनजर रूस के अरबपति और चेल्सी फुटबॉल क्लब के मालिक रोमन अब्रामोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति का खत लेकर पुतिन के पास पहुंचे थे। इस खत में जेलेंस्की ने उन शर्तों के बारे में बताया था, जिससे युद्ध रोका जा सकता है। इस पर भड़कते हुए पुतिन ने कहा कि मैं यूक्रेन को बर्बाद कर दूंगा। पुतिन के इस बयान से साफ है कि वे जिस रणनीति को लेकर निकले थे, उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। पुतिन इस बात को जानते हैं कि इस समय अगर उन्होंने कदम वापस लिए तो दुनियाभर में उनका विरोध और तेज हो जाएगा। साथ ही अमेरिका और अन्य देशों को दबाव बनाने का मौका मिल जाएगा। हालांकि, यूरोपीय देश ब्रिटेन की तरफ से रूस को एक ऑफर दिया गया है। ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस ने कहा कि अगर रूस जंग को खत्म करता है और यूक्रेन से अपनी सेना को वापस बुलाता है तो ब्रिटेन रूस और उसकी कंपनियों पर लगे प्रतिबंध हटा देगा। मगर अभी पुतिन किसी की सुनने वाले नहीं हैं। पिछले दिनों यूक्रेन पर हमले रोकने के लिए रूस ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के आदेश की अनदेखी कर अपनी हठधर्मिता दिखाई थी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के आदेश के बावजूद यूक्रेन के शहरों पर उसकी सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। रोजाना बेगुनाह नागरिक मारे जा रहे हैं। पूरी दुनिया को ठेंगा दिखाते हुए रूस जिस आक्रामकता से यूक्रेन को रौंदता जा रहा है, उससे साफ है कि उसे अब किसी की भी परवाह नहीं। चीन ने जिस तरह की नीति दिखाई है, जाहिर है वह रूस के समर्थन की ही है। भारत सहित कुछ देश तटस्थ बने हुए हैं और दोनों पक्षों से शांति की अपील कर रहे हैं। खतरा ज्यादा इसलिए भी बढ़ गया है कि परमाणु हमले करने वाली सैन्य कमान को पुतिन पहले ही तैयार रहने को कह चुके हैं। हालांकि यह उतना आसान भी नहीं है। पुतिन इस बात को भली भांति समझते हैं कि ऐसा करना पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंकने जैसा होगा। यों इस जंग में रूस को पसीना आने लगा है। बड़ी संख्या में रूसी सैनिक मारे गए हैं। अगर रूसी सेना कीव पर कब्जा नहीं कर पाई है तो इससे यूक्रेन की सैन्य ताकत के साथ उसके और नागरिकों के मनोबल का भी पता चलता है। यूक्रेन की सेना भी पूरी ताकत से रूस को जवाब दे रही है। रूस को लग रहा था कि जंग कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। पर ऐसा हुआ नहीं। पुतिन इस वक्त युद्धोन्माद में डूबे हैं। ऐसे में रूस के परमाणु हथियार के इस्तेमाल करने की आशंका से कैसे इनकार किया जा सकता है? रूसी मिसाइलों और बमों से यूक्रेन के कई शहर खंडहर हो चुके हैं। जान बचाने के लिए 50 लाख लोग इस देश से पलायन कर चुके हैं। कहने को रूस और यूक्रेन के बीच वार्ताओं के कई दौर भी हो चुके हैं, लेकिन सब बेनतीजा। रूसी राष्ट्रपति एक ही जिद पर तुले हैं कि यूक्रेन किसी भी सूरत में नाटो का सदस्य नहीं बने और स्वीडन, स्विटजरलैंड जैसे देशों की तरह सीमित सेना रखे। यूक्रेन के सामने अस्तित्व का गंभीर सवाल है। यूक्रेन अगर वह रूस की इस शर्त के आगे झुक गया तो उसकी स्थिति एक गुलाम देश जैसी हो जाएगी। इसलिए यूक्रेन आसानी से हार कैसे मान ले! रूस-यूक्रेन की जंग का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर साफ दिखने लगा है। युद्ध के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमराने को लेकर चिंता इसलिए भी बढ़ गई है कि ज्यादातर देश महामारी की मार से अभी तक उबरे भी नहीं थे कि दूसरा संकट सिर पर आ गया। युद्ध और महामारी जैसी विपत्तियां मानव जीवन को कैसे तबाह कर देती हैं, यह अब छिपा नहीं रह गया है। महामारी की वजह से महंगाई और बेरोजगारी ने किसको नहीं रुलाया! अब फिर वैसे ही हालात बनते दिख रहे हैं। रोजाना नए रिकार्ड बनाता कच्चा तेल सबसे बड़ा संकट पैदा कर रहा है। कच्चा तेल महंगा होते ही सरकारें पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने का कदम उठाती हैं और इसका सीधा हर तरह के कारोबार से लेकर आम जीवन पर पड़ता है। भारत दुनिया के कई देशों को दवाइयों से लेकर कपड़े, मशीनें, कलपुर्जे, इलेक्ट्रानिक सामान, चाय, काफी, वाहन आदि का निर्यात करता है। साथ ही दालें, खाने के तेल, उद्योगों के लिए कच्चा माल आयात करता है। वैश्विक कारोबार में हर देश इसी तरह एक दूसरे के सहारे टिका हुआ है। ऐसे में महंगा कच्चा तेल नौवहन की लागत बढ़ाता है और फिर इसका असर निर्यात-आयत पर पड़ता दिखता है। लागत बढ़ने से स्थानीय कारोबारी प्रभावित होते हैं और महंगाई बढ़ती है। रूस को वैश्विक भुगतान व्यवस्था से अलग-थलग कर देने के बाद कारोबारियों को पैसे फंसने का भी डर सता रहा है। जंग के असर से भारत भी अछूता कैसे रह सकता है! सरकार और रिजर्व बैंक दोनों ही इस संकट को बखूबी समझ रहे हैं।

राजनीति का 'बुलडोज़र काल'

किसी सच्चे संत,महात्मा,त्यागी अथवा योगी को यदि 'बुल्डोज़र बाबा' की उपाधि से नवाज़ा जाये तो मुझे नहीं लगता कि यह उपाधि उसे पसंद आयेगी या अच्छी लगेगी। क्योंकि निश्चित रूप से बुलडोज़र विध्वंस तोड़ फोड़ का ही प्रतीक है। और किसी संत योगी का विध्वंस से आख़िर क्या वास्ता हो सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ को भी जब टी वी व समाचारपत्रों में 'बुलडोज़र बाबा' के नाम से उद्घृत किया जाता था तो ऐसा ही लगता था कि शायद यह 'उपाधि ' उन्हें भी ठीक न लगती हो। परन्तु पिछले दिनों जब योगी आदित्य नाथ को उनके मुख्यमंत्री पद की दूसरी बार शपथ ग्रहण करने से पूर्व गत 20 मार्च को ही उनके गोरखपुर प्रवास के दौरान कुछ व्यवसायियों द्वारा चांदी का बुलडोज़र भेंट किया गया और योगी जी प्रसन्नचित मुद्रा में चांदी के उस बुलडोज़र को स्वीकार करते हुये नज़र आये तो मेरी ग़लतफ़हमी दूर हो गयी। यह समझने में देर नहीं लगी कि योगी जी को बुलडोज़र बाबा की उपाधि से कोई आपत्ति नहीं बल्कि शायद वे स्वयं को इस उपाधि से गौरवान्वित ही महसूस कर रहे हैं। और जब सूत्रों से यह पता चला कि योगी को चांदी का बुलडोज़र भेंट करने वाले व्यापारी भी गोरख पीठ से ही जुड़े हुए लोग हैं फिर इस निष्कर्ष पर पहुँचने में भी कोई हर्ज नहीं कि यह 'बुलडोज़र भेंट' भी प्रायोजित एवं नियोजित था।

बहरहाल 'बुलडोज़र' की लोकप्रियता अब उत्तर प्रदेश से सटे राज्य मध्य प्रदेश में भी पहुँच चुकी है। उत्तर प्रदेश में 'बुलडोज़र बाबा' तो मध्य प्रदेश में 'बुलडोज़र मामा' के पोस्टर लगने शुरू हो चुके हैं। मामा के नाम से लोकप्रिय हो चुके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगता है 'बुलडोज़र मामा ' की उपाधि से उतना ही ख़ुश हैं जितना कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्य नाथ 'बुलडोज़र बाबा ' की उपाधि से प्रसन्न नज़र आते हैं। मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर भाजपा कार्यकर्त्ता मुख्यमंत्री चौहान और बुलडोज़र छपे फ़्लेक्स लगाने में जुटे हैं।उधर 'बुलडोज़र मामा ' की उपाधि मिलते ही चौहान बुलडोज़र की तरह गरजने भी लगे हैं। मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुये उनकी 'बुलडोज़री भाषा' पर भी ग़ौर कीजिये - मुख्यमंत्री चौहान फ़रमाते हैं कि- 'मध्यप्रदेश में जितने गुंडे और अपराधी हैं, वो भी सुन लें। अगर ग़रीब कमज़ोर की तरफ़ हाथ उठे तो मकान को मैदान बना दूंगा। गुंडागर्दी करने वालों, मध्यप्रदेश की धरती से तुम्हारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। सबको कुचल दिया जाएगा। मामा का बुलडोज़र चला है, जो अब रुकेगा नहीं, जब तक गुंडों-बदमाशों को दफ़न नहीं कर देगा। एमपी के सारे अपराधी सुन लो, किसी ग़रीब या कमज़ोर पर हाथ उठाया तो तुम्हारे घर उखाड़कर उसे मिट्टी में मिला दूंगा. तुम्हें यहां शांति से जीने नहीं दूंगा।' आदि आदि ....मुझे नहीं लगता कि इस तरह की शब्दावली का प्रयोग पहले भी राजनेताओं द्वारा किया गया हो।

किसी भी अपराधी या बलात्कारी के विरुद्ध प्रशासन को निश्चित रूप से सख़्त व न्यायसंगत कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिये। ऐसा करते समय न तो किसी का धर्म या जाति देखकर किसी तरह का पक्षपात करना चाहिये न ही किसी का रुतबा अथवा पद देखना चाहिये। 'राम राज' लाने का दावा करने वाले शासन को सबके लिये एक समान न्याय सुनिश्चित करना चाहिये। किसी शासक को अपनी छवि किसी आक्रामक या दबंग नेता के बजाये एक सौम्य,विवेकपूर्ण,लोक सेवक तथा मृदुभाषी नेता के रूप में स्थापित करनी चाहिये। जहाँ तक किसी अपराधी का घर ढहाने का प्रश्न है तो इस बात को भी मद्देनज़र रखना चाहिये कि जिस मकान पर सिर्फ़ इसलिये बुलडोज़र चलाया जा रहा है कि इस मकान में कोई अपराधी रहता है,तो इससे पहले यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि आरोपी उस मकान का मालिक है भी अथवा नहीं ? इस मानवीय पक्ष को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि किसी आरोपी के बुज़ुर्ग माता पिता और भाई बहन का क्या दोष जिन्हें उनकी नालायक़ औलाद के चलते घर से बेघर किया जाये ? देश की अदालतें भी किसी के जघन्य अपराधी साबित होने के बावजूद किसी के मकान पर बुलडोज़र चलाने का आदेश नहीं देतीं। क्योंकि वह न्यायालय है जहाँ इंसाफ़ मिलता है। अपराध करने वाले को सज़ा मिलती है न कि उसका मकान ढहा कर उसके बूढ़े मां बाप और परिजनों को भी बेघर व बेसहारा कर दिया जाये ?

आज सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के अधिकांश राजनैतिक दलों में अपराधी भरे पड़े हैं। अभी ज़्यादा समय नहीं बीता है जबकि सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने अपने देश की संसद में भारतीय राजनीतिज्ञों का 'काला चिट्ठा' खोला था। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के हवाले से ही उन्होंने यह आंकड़े रखे थे कि किन किन आरोपों में संलिप्त कितने 'महामहिम ' इस समय भारतीय संसद की रौनक़ बढ़ा रहे हैं। क्या 'सरकार का बुलडोज़र' कभी इन 'महामहिम' के मकानों की तरफ़ भी गया ? उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में कई ऐसी इमारतों को भी बुलडोज़र से धराशायी करने की ख़बरें मिलीं जिन्हें या तो सरकारी ज़मीन पर क़ब्ज़ा बताया गया या अवैध निर्माण बताकर गिराई गयीं। बेशक सरकार व प्रशासन के पास निर्धारित नोटिस दिये जाने के बाद इस तरह के अवैध निर्माण गिराये जाने का प्रावधान है। परन्तु इस बात की भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इस तरह के अवैध निर्माणों में स्थानीय सम्बद्ध विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों की भी मिलीभगत होती है। प्रशासन के लोग आख़िर इस तरह के अवैध निर्माणाधीन भवन को आंखे मूँद कर क्यों देखते रहते हैं ? अवैध निर्माणों को प्रोत्साहन देने वाले भ्रष्टाचारी लोग भी क्या सज़ा के हक़दार नहीं ?

लगता है राजनीति का सौम्य-शिष्ट व उदार काल अब समाप्त हो चुका है। अब ठोक दो,बक्कल उतार दो,गर्मी उतार दो, मकान को मैदान बनाडालो,कुचल दो जैसे 'आक्रामक संवाद भाषा' का दौर शुरू चुका है। जिस देश में पंडित नेहरू की पहचान 'गुलाब के फूल' से होती थी उसी देश में अब 'बुलडोज़र बाबा' और 'बुलडोज़र मामा' की उपाधि पाकर राजनेता प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं। राजनीति के इस विषम दौर को राजनीति का 'बुलडोज़र काल' कहना ग़लत नहीं होगा।(लेखक- तनवीर जाफ़री/ईएमएस)

विधायको को सिर्फ एक पेंशन का ऐतिहासिक कदम!

देश की जनता लंबे समय से यह मांग करती रही है कि विधायको व सांसदों की पेंशन या तो पूरी तरह से बंद हो या फिर उन्हें सिर्फ एक ही पेंशन मिले ,लेकिन आमजन की इस मांग को अनसुना कर जितनी बार भी सांसद या विधायक रहे उतनी ही पेंशन लेकर देश पर आर्थिक बोझ जारी है।इस बोझ को पहली बार पंजाब में हाल ही में बनी आम आदमी पार्टी की सरकार ने समझा है।इस सरकार ने हर कार्यकाल के लिए पूर्व विधायकों की पेंशन की प्रथा खत्म करते हुए, अब सिर्फ एक कार्यकाल के लिए पेंशन जारी रखने का ऐलान किया है। पूर्व विधायकों को पंजाब में 75 हजार रुपये पेंशन मिलेगी।पंजाब सरकार ने विधायकों की पेंशन को लेकर यह बड़ा फैसला लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घोषणा की है कि पूर्व विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए पेंशन मिलेगी। पंजाब ही नही देशभर में अभी तक प्रत्येक कार्यकाल के लिए पेंशन मिलती रही है। पंजाब सरकार के अधिकारियों को 'एक विधायक-एक पेंशन' योजना को लागू करने का निर्देश दिया गया है।अभी तक कई बार चुने गए विधायकों को पेंशन के रूप में कई बार की ही पेंशन के रूप में लाखों रुपये मिल रहे थे। उनमें से कुछ जो सांसद भी रहे हैं, उन्हें केंद्र और राज्य दोनों तरह की पेंशन मिल रही है। इस फैसले से राज्य सरकार के करीब 80 करोड़ रुपये बचेंगे।भगवंत मान ने कहा कि, ''लोगों की सेवा के वादे के साथ वोट मांगने वाले विधायकों को 3.5 लाख रुपये, 4.5 लाख रुपये और यहां तक कि 5.25 लाख रुपये मासिक पेंशन मिल रही थी। नए फैसले के साथ सरकार की योजना पांच साल में 80 करोड़ रुपये बचाने की है।बचाए गए धन का उपयोग कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जाएगा।''उदाहरण के तौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजिंदर कौर भट्टल, लाल सिंह और पूर्व अकाली दल नेता सरवन सिंह फिल्लौर को 3.25 लाख रुपये जबकि रवि इंदर सिंह और बलविंदर सिंह भिंडर को हर महीने 2.75 लाख रुपये पेंशन के रूप में मिलते हैं।पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सरकार को पत्र लिखा था कि वह सरकार से किसी भी तरह की पेंशन का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें कोई पेंशन दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा था कि पैसे का इस्तेमाल लोक कल्याण की योजनाओं के लिए किया जाना चाहिए।हरियाणा सरकार ने कुछ साल पहले पूर्व विधायकों के लिए एक साथ कई पेंशन खत्म कर दी थी। पंजाब में अमरिंदर सिंह की सरकार ने उस वक्त पड़ोसी राज्य से संकेत लेते हुए पेंशन नीति को बदलने पर चर्चा की थी। लेकिन कभी कोई निर्णय उनके द्वारा नहीं लिया गया।

पंजाब सरकार के नियमों के अनुसार विधायक को पहले कार्यकाल के लिए 75 हजार रुपये और उसके बाद हर अन्य कार्यकाल के लिए 50 हजार रुपये पेंशन दिए जाने का प्रावधान है।पंजाब में इस समय र 275 पूर्व विधायक अपने अलग-अलग कार्यकाल के लिए पेंशन ले रहे हैं। इसमें राज्य के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत एक दर्जन पूर्व विधायक शामिल हैं जिन्हें कार्यकाल के हिसाब से 5-6 पेंशन तक एक साथ मिल रहीं हैं।पंजाब में मुख्यमंत्री का मासिक वेतन (भत्तों समेत) डेढ़ लाख रुपये बनता है। पूर्व विधायकों में पांच बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल इस समय 11 पेंशन के हकदार हैं और उन्हें पेंशन की कुल राशि 5,76,150 रुपये मिलती थी। हालांकि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर पेंशन न लेने की घोषणा की है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्टल, पूर्व मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, लाल सिंह और परमिंदर सिंह ढींढसा समेत पंजाब के कई पूर्व विधायक ऐसे हैं जिन्हें उनके कार्यकाल के हिसाब से 5-6 पेंशन मिलती हैं। इसकी कुल रकम 2,75,550 रुपये से 3,25,650 रुपये बनती है।पंजाब राज्य विधान मंडल सदस्य (पेंशन व मेडिकल सुविधा) एक्ट 1977 और पंजाब राज्य विधान मंडल सदस्य (पेंशन व मेडिकल सुविधा) एक्ट 1984 में संशोधन के साथ पंजाब एक्ट नंबर 30 ऑफ 2016 के तहत नोटिफिकेशन जारी करके ऐसा प्रावधान कर दिया गया कि पूर्व विधायक को उनके पहले कार्यकाल के लिए पेंशन के रूप में 15000 रुपये और अगली प्रत्येक टर्म के लिए 10000 रुपये से आगाज होगा। इस रकम में पहले 50 फीसदी डीए मर्ज होगा और उसके बाद बनने वाली कुल रकम में फिर से 234 फीसदी महंगाई भत्ता जुड़ जाएगा। इस तरह पूर्व विधायकों को जबरदस्त लाभ हुआ, क्योंकि 15000 + 7500 (50 फीसदी डीए)= 22500 रुपये रकम बनी। 22500+52650 (234 फीसदी डीए) रुपये यानी कुल 75150 रुपये पेंशन बनती हैं। सूबे के 275 पूर्व विधायकों को वर्ष 2017 से हर साल 37 करोड़ और पांच वर्ष में 186 करोड़ रुपये पेंशन के तौर पर दिए जा रहे थे लेकिन जिस एक्ट के आधार पर यह पेंशन तय की गई, ऐसा कोई प्रावधान किसी भी एक्ट में था ही नहीं। पंजाब की अकाली-भाजपा सरकार ने अक्तूबर 2016 में पूर्व विधायकों की पेंशन को पहले कार्यकाल में 15000 रुपये और बाद के कार्यकाल के लिए 10-10 हजार रुपये का प्रावधान करते हुए साफ कर दिया था कि इस राशि में महंगाई भत्ता अन्य सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते के अनुसार ही जुड़ेगा। अगर इस तरीके से पेंशन तैयार होती तो 15000 रुपये और 28 फीसदी डीए को मिलाकर 19200 रुपये ही पूर्व विधायको को मिल पाते। लेकिन शासन स्तर की गई इस त्रुटि का नतीजा यह हुआ कि पूर्व विधायकों को 19200 रुपये की जगह 75150 रुपये पेंशन मिलती रही। इस तरह पांच साल के दौरान सरकारी खजाने से लगभग 192 करोड़ रुपये अधिक निकाल लिए गए। जिससे पंजाब सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ता चला गया। (लेखक- डॉ श्रीगोपाल नारसन /ईएमएस)

गैर प्रजातंत्री प्रयास : स्वतंत्र संवैधानिक संगठनों पर सरकारी अतिक्रमण कहाँ तक उचित....?

हमारे देश के संविधान पुस्तिका को सिर्फ 'शपथ' तक सीमित रखने का सरकारी प्रयास किस गैर प्रजातंत्रीय दिशा में देश को लेजा रहा है, इसका एक उदाहरण हमारे संवैधानिक स्वतंत्र संगठन है, जिन पर अवैध अतिक्रमण कर अपनी 'बपौती' मान सरकार कुण्डली मारकर बैठी हुई है और इसी कारण ये स्वतंत्र संवैधानिक संगठन सरकार की हडवादिता व स्वार्थ के चलते गैर संवैधानिक व अप्रजातांत्रिक कार्य करने को मजबूर है।

हमारे देश में चुनाव आयोग सीबीआई, लोकसेवा आयोग आदि ऐसे संवैधानिक संगठन है, जो संवैधानिक रूप से स्वतंत्र व निष्पक्ष भाव से अपना कार्य सम्पन्न कर सकते है और इन्होंने देश की आजादी के बाद उनके गठन के पश्चात कई वर्षो तक निष्पक्ष व स्वतंत्र रूप से संविधान की भावना के अनुरूप कार्य किया भी है, किंतु पिछले पांच दशक से (लगभग आपातकाल के बाद से) देश पर सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों पर कुदृष्टि पड़ी और धीरे-धीरे अब इन स्वतंत्र संवैधानिक संगठनों को सरकार पर काबिज राजनीतिक दलों के हाथों की कठपुतली बनने को मजबूर होना पड़ा। जिसके पश्चिम बंगाल के चुनाव, वहां का ताजा नरसंहार तथा देश के अन्य भागों में घटी घटनाएं व चुनाव से जुड़ी विसंगतियां ताजा उदाहरण है। और अब तो इन संवैधानिक संगठनों का सरकार द्वारा इतना अधिक दुरूपयोग किया जा रहा है कि जिसकी विश्व के किसी देश से तुलना नहीं की जा सकती।

हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के दो साल बाद यह याद आया था कि उन्होंने 2014 के चुनावों के समय ''एक राष्ट्र-एक चुनाव'' तथा समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था, उन्होंने उसी समय अपने इन दोनों वादों को शीघ्र मूर्तरूप देने का संकल्प भी लिया था, किंतु इस संकल्प को भी छः साल गुजर गए, मोदी जी 2019 का लोकसभा चुनाव भारी बहुमत से जीतकर पुनः प्रधानमंत्री भी बन गए किंतु ये देशहित के दो वादे आज भी वहीं के वहीं है, क्योंकि इनके लागू करने में 'सत्तारूढ़ दल' को अपना वोट बैंक कम होने की चिंता जो सता रही है, इसी कारण न तो देश का लाखों-करोड़ों रूपया बचाने वाले ''एक राष्ट्र-एक चुनाव'' का वादा पूरा हो पा रहा है और न ही पूरे देश के नागरिकों को समानता के एक सूत्र में पिरोने वाले 'समान नागरिक संहिता' का वादा पूरा हो पा रहा है, ये दोनों महत्वपूर्ण वादें सत्ता की राजनीति के कोहरे में खोकर रह गए।

यदि हम एक राष्ट्र-एक चुनाव की बात करें, तो यह कोई भाजपा द्वारा पैदा किय गया चुनावी नारा नही है, देश की आजादी के बाद 1951 में हुए पहले आम चुनाव से लेकर 1967 तक देश में लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन 1969 में कुछ राज्य विधानसभाऐं भंग की गई और वहां राष्ट्रपति शासन लागू किए गए, उसके बाद से लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के चुनाव उनकी अवधि पूरी होने के हिसाब से अलग-अलग होने लगे उसका परिणाम आज यह दिखाई दे रहा है कि हर वर्ष किसी न किसी राज्य विधानसभा के चुनाव या उपचुनाव होते है और उस पर देश का अपार धन व समय खर्च हो रहा है, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल भी चुनावों में व्यस्त हो जाते है जिससे सरकार द्वारा किए जाने वाले जनहित के कार्य नहीं हो पाते और सत्तारूढ़ दल भी राजनीतिक स्पद्र्धा में व्यस्त हो जाता है। अब आज देश की मौजूदा स्थिति यह है कि अभी-अभी पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव निपटे है, इनके बाद इसी वर्ष के अंत में गुजरात, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव होगें, इसके उपरांत अगले वर्ष फरवरी में नागालैण्ड, त्रिपुरा, मेघालय में चुनाव कराये जायेगें, मई 2023 में कर्नाटक में तथा नवम्बर में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ व मिजोरम में विधानसभा चुनाव होंगे, इसके महीनें बाद अर्थात् दिसम्बर 2023 में राजस्थान व तेलंगाना की विधानसभाओं के तथा अप्रैल-मई 2024 में लोकसभा के साथ आंध्रप्रदेश, ओडिशा, अरूणाचल तथा सिक्कीम राज्य विधानसभाओं के चुनाव होगें महाराष्ट्र व हरियाणा में अक्टूबर 2024 तथा झारखण्ड में नवम्बर-दिसम्बर तथा इसके बाद फरवरी 2025 में दिल्ली व नवम्बर-दिसम्बर में बिहार के चुनाव होगें। इस तरह पूरे देश के राज्यों के चुनाव कार्यकाल अलग-अलग है तथा इसी कारण राजनीतिक कृत्यों में व्यस्त होने के कारण न तो सत्तारूढ़ दल कोई जनहित के सरकारी कार्य कर पाते है और न ही प्रतिपक्षी दल अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाते है और इससे प्रभावित होता है बैचारा आम नागरिक या आम वोटर।

इसीलिए इस मुद्दें को भाजपा ने चुनावी नारा बनाया था, जिसे वह अब तक मूर्तरूप नही दे पाई है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी इसके लिए वचनबद्ध है। यही स्थिति समान नागरिक संहिता की है, इसके लागू होने से कहीं कोई सम्प्रदाय विशेष का 'वोट बैंक' कहीं नाराज न हो जाए, इस भय से सत्तारूढ़ दल इसे लागू नहीं कर पा रहा है।

अरे.... जब आप जिन वादों को राजनीतिक मजबूरी में पूरे नहीं कर पाते तो फिर उन्हें राजनीति में लपेट कर 'मीठा व्यंजन' समझ कर परोसते ही क्यों हो? यह एक विचारणीय बिन्दु है। (लेखक- ओमप्रकाश मेहता/ईएमएस)

आज का इतिहास 31मार्च

1492 स्पेन में यहूदियों को तीन माह में ईसाई धर्म स्वीकार करने या देश छोड़ने का आदेश दिया गया.
1606 पोलैंड और रोम ने तुर्की के खिलाफ गठबंधन किया.
1809 रूसी लेखक निकोलाई गोगोल का जन्म हुआ .
1854 अमेरिका और जापान के बीच एक समझौते के तहत जापान ने अपने बंदरगाह बाहरी दुनिया के लिए खोल दिये.
1889 एफिल टावर खोला गया.
1913 तुर्की ने बल्गारिया से शांति संधि के लिए महाशक्तियों की सलाह को मान ली.
1936 ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड को हमला होने पर मदद करने का वचन दिया.
1941 द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने उत्तर अफ्रीका में जवाबी कारवाई की.
1964 विधुत ट्राम कार मुम्बई में अंतिम बार चली.
1966 दक्षिण अफ्रीका में प्रधानमंत्री हैड्रिक वरबुर्ड की पार्टी को चुनावों में भारी सफलता मिली.
1980 अंतिम आई.सी.एस.अधिकारी निर्मल मुखर्जी रिटायर हुए थे.
1987 अल सल्वाडोर के एक सैन्य ठिकाने पर छापामारों के हमले में 43 सैनिक मारे गये.
1988 आस्ट्रेलिया के भूतपूर्व प्रधानमंत्री सरविलियम मेक्मोहन का निधन.
1989 तुर्की के प्रझानमंत्री तुर्गत ओजल ने अपने भाई भतीजे सहित बारह मंत्रियों को हटा दिया.
2001 सचिन तेंदुलकर एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10 हजार रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने.
2005 हरियाणा के दो मंत्री ओमप्रकाश जिंदल व सुरेंद्र सिंह व पायलट का हेलिकॉप्टर दुर्घटना में निधन.

दैनिक पंचांग

31 मार्च 2022 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

ग्रह स्थिति		लग्नारंभ समय	
सूर्य	मीन में	मेष	06.40 बजे से
चंद्र	मीन में	वृष	08.20 बजे से
मंगल	मकर में	मिथुन	10.18 बजे से
बुध	कुंभ में	कर्क	12.31 बजे से
गुरु	कुंभ में	सिंह	14.47 बजे से
शुक्र	मकर में	कन्या	16.59 बजे से
शनि	मकर में	तुला	19.10 बजे से
राहु	वृष में	वृश्चिक	21.25 ब.से
केतु	वृश्चिक में	धनु	23.41 बजे से
राहुकाल 1.30 से 3.00 बजे तक		मकर	01.46 बजे से
		कुंभ	03.32 बजे से
		मीन	05.05 बजे से

गुरुवार 2022 वर्ष का 90 वां दिन **दिशाशूल** दक्षिण **ऋतु** बसंत। **विक्रम संवत्** 2078 **शक संवत्** 1944 **मास** चैत्र (दक्षिण भारत में फाल्गुन) **पक्ष** कृष्ण **तिथि** चतुर्दशी 12.23 बजे को समाप्त। **नक्षत्र** पूर्वाभाद्रपदा 10.31 बजे को समाप्त। **योग** शुक्ल(शुक्र) 11.07 बजे को समाप्त। **करण** शकुनि 12.23 बजे तदनन्तर चतुष्पद 00.05 बजे रात्र को समाप्त। **चन्द्रायु** 24.3 घण्टे **रवि क्रान्ति** उत्तर 04° 04' **सूर्य** उत्तरायन **कलि अहर्गण** 1871204 **जूलियन दिन** 2459669.5 **कलियुग संवत्** 5123 **कल्पारंभ संवत्** 1972949123 **सृष्टि ग्रहारंभ संवत्** 1955885123 **वीरनिर्वाण संवत्** 2548 **हिजरी सन्** 1443 **महीना** सावान **तारीख** 27 **विशेष** दर्श अमावस्या, अन्वाधान।

दिन का चौघड़िया			रात का चौघड़िया		
शुभ	05.54 से	07.22 बजे तक	अमृत	05.40 से	07.11 बजे तक
रोग	07.22 से	08.51 बजे तक	चर	07.11 से	08.43 बजे तक
उद्वेग	08.51 से	10.19 बजे तक	रोग	08.43 से	10.15 बजे तक
चर	10.19 से	11.47 बजे तक	काल	10.15 से	11.47 बजे तक
लाभ	11.47 से	01.15 बजे तक	लाभ	11.47 से	01.19 बजे तक
अमृत	01.15 से	02.43 बजे तक	उद्वेग	01.19 से	02.51 बजे तक
काल	02.43 से	04.11 बजे तक	शुभ	02.51 से	04.23 बजे तक
शुभ	04.11 से	05.40 बजे तक	अमृत	04.23 से	05.55 बजे तक

चौघड़िया शुभाशुभ- शुभत्व श्रेष्ठ शुभ, अमृत व लाभ, **मध्यम** चर, **अशुभ** उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अतः आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें। ■Jagrutidaur.com, Bangalore

शब्द पहेली - 7241

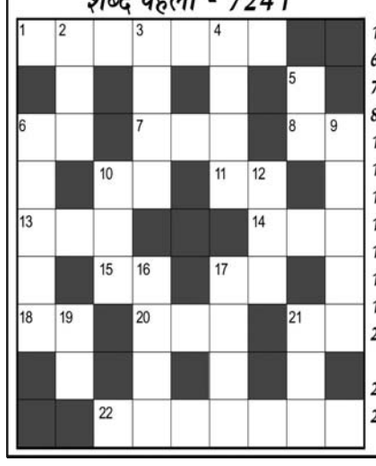

बाएँ से दाएँ

1.भगवान, ईश्वर,रब-7
6.रुपये का सोलहवां भाग-2
7.मध्यप्रदेश का एक भाग-3
8.मूल्य,कीमत,दर-2
10.जी,इच्छा,चित-2
11.नलका,टोंटी-2
13.बारीक,सूक्ष्म-3
14.रेखा,लाइन-3
15.रग,नाड़ी-2
17.अधिकार -2
18.वध,कत्ल,मर्डर-2
20.दौड़ने वाला,धावक (अंग्रेजी-3)
21.एक आंख वाला-2
22.निंदा करना,प्रतिष्ठा खंडित करना-4,3

ऊपर से नीचे

2.निर्माण,बनाना-3
3.एक संगीतकार-4
4.गाड़ी चलानेवाला-4
5.नखरा-2
6.आरामदेय-5
9.इच्छा पूरी करना-2,3
10.चिंतन-3
12.उत्साह,जिज्ञासा-3
16.हद,सीमा,बार्डर-4
17.हमेशा,सदैव-4
19.बलिदान,परित्याग, विरक्ति-2
21.नास्तिक (उर्दू-2)

शब्द पहेली-7240 का हल

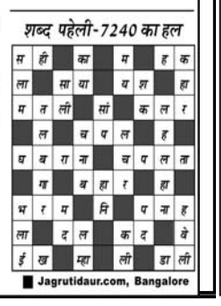

■Jagrutidaur.com, Bangalore

खेल - समाचार

ओसाका मियामी ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में पहुंची

मियामी (ईएमएस)। जापान की महिला टेनिस स्टार नाओमी ओसाका मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गईं हैं। विश्व की पूर्व नंबर एक खिलाड़ी ओसाका ने क्वार्टरफाइनल मुकाबले में अमेरिका की डेनियल कोलिंस को सीधे सेटों में 6-2, 6-1 से हराया। अब मियामी ओपन के खिताबी मुकाबले में जगह बनाने के लिए ओसाका का मुकाबला सेमीफाइनल में स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेनकिक से होगा।

इस जीत के साथ ही ओसाका टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी जापानी महिला टेनिस खिलाड़ी

भारत भरेगा दुनिया का पेट, गेहूं का रिकॉर्ड निर्यात

मुंबई (ईएमएस)। रूस-यूक्रेन जंग के कारण दुनियाभर में गेहूं की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। भारत के पास गेहूं के बफर स्टॉक होने की खबरों से कीमतों पर लगाम लगी है। भारत के पास फिलहाल 12 मिलियन टन निर्यात लायक गेहूं का स्टॉक है। इस साल भारत दुनिया के उन देशों को गेहूं निर्यात करेगा, जो पहले रूस और यूक्रेन से गेहूं लिया करते थे। इन देशों में दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं आयातक मिस्र भी शामिल है।

विशेषज्ञों का कहना है कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में विश्वभर में रूस-यूक्रेन युद्ध, अकाल और मांग बढ़ने के कारण भारी बढ़ोतरी हुई है। वहीं शिकागो में बेंचमार्क गेहूं के भाव 13.635 प्रति बुशेल के उच्चतम स्तर को पिछले महीने ही छू चुके हैं। भारत के गेहूं निर्यात करने से विश्व बाजार में गेहूं की सप्लाई बढ़ेगी।

भारत चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है। सर्वे के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत के पास निर्यात करने लायक 12 मिलियन टन गेहूं है। अमरीकी कृषि विभाग के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने 8.5 मिलियन टन गेहूं का निर्यात किया था। सप्लाई कम होने और गेहूं की कीमतें बढ़ने के साथ ही बहुत से देश पहली बार भारत से गेहूं का आयात करने वाले है। पिछले पांच फसली सीजन से भारत में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन हो रहा है। इस कारण भारत के पास गेहूं का पर्याप्त अतिरिक्त भंडार है, जिस गेंहू का निर्यात कर सकता है। इस बार का गेहूं कटाई सीजन भी शुरू हो गया है। इस बार भी रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है।

गेहूं निर्यात को लेकर भारत की गेहूं के सबसे बड़े आयातक मिस्र के साथ बातचीत लगभग फाइनल हो चुकी है। इसके अलावा चीन, तुर्की, बोसनिया, सूडान, नाइजीरिया और ईरान भी गेहूं लेने के लिए भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। पिछले दस महीनों में ही भारत के गेहूं निर्यात में चार गुणा बढ़ोतरी हुई है। बदली हुई वैश्विक परिस्थितियों में भारत को बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के अलावा अब अफ्रीका और मिडल ईस्ट रीजन में भी निर्यात गेहूं निर्यात के मौके मिलेगा।

सिंगापुर स्थित अनाज की बड़ी आयात-निर्यात फर्म एग्रीकूप इंटरनेशनल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कि भारत के गेहूं निर्यात करने से अंतरराष्ट्रीय मार्केट में गेहूं की सप्लाई कुछ सामान्य होगी। फिलहाल सप्लाई बहुत कम है। भारत के गेहूं निर्यात करने की संभावनाओं ने ही कीमतों पर कुछ लगाम लगेगी है। अगर भारत गेहूं निर्यात नहीं करता,तब गेहूं की कीमतों में भारी उछाल आता। हालात यह है कि हर गेहूं आयातक देश भारत से गेहूं लेने पर विचार कर रहा है। भारतीय गेहूं को लेकर जितना उत्साह इस बार देखा जा रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया है।

शेयर बाजार तेजी के साथ बंद

मुंबई (ईएमएस)। मुम्बई शेयर बाजार में सप्ताह के तीसरी दिन बुधवार को भी बढ़त जारी रही। बाजार में यह तेजी दिग्गज कंपनियों इन्फोसिस, एचडीएफसी लि., एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में लिवाली (खरीददारी) के साथ ही दुनिया भर के बाजारों से मिले अच्छे संकेतों से आई है। दिन भर के कारोबार के बाद तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 740.34 अंक करीब 1.28 फीसदी की बढ़त के साथ ही 58,683.99 अंक पर बंद हुआ जबकि कारोबार के दौरान एक समय यह उछलकर 58,727.78 अंक तक पहुंच गया था।

वहीं इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 172.95 अंक तकरीबन एक फीसदी की बढ़त के साथ ही 17,498.25 अंक पर बंद हुआ।

सेंसेक्स के तीस शेयरों में से बजाज फिनसर्व, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, पावर ग्रिड, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, नेस्ले, मारुति, रिलायंस इंडस्ट्रीज लि के शेयर लाभ में रहे। वहीं दूसरी ओर आईटीसी, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, भारती एयरटेल और टाइटन के शेयर नीचे आये हैं। बाजार जानकारों के अनुसार रुस-यूक्रेन संकट के हल होने की उम्मीद से भी बाजार में सकारात्मक माहौल है।

इससे घरेलू बाजार को भी बल मिला है। इसके अलावा कच्चे तेल और जिंसों के दाम में कमी से भी बाजार को बल मिला। इससे कंपनियों को मार्जिन पर दबाव कम करने में सहायता मिलेगी।''

शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) मंगलवार को शुद्ध लिवाल रहे और उन्होंने 35.47 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

रत्न एवं आभूषण क्षेत्र 100 अरब डॉलर निर्यात लक्ष्य तय करें: गोयल

दुबई (ईएमएस)। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रत्न एवं आभूषण निर्यातकों से आने वाले वर्षों में सालाना 100 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य तय करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में निर्यात की दृष्टि से काफी संभावनाएं हैं। गोयल ने उद्योग से आग्रह किया कि वे बेहतर विपणन उपकरण और डिजाइन के जरिए निर्यात बढ़ाएं। गोयल ने रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद (जीजेईपीसी) के निर्यात सदस्यों को संबोधित करते हुए कक्कि ?कि आइए 100 अरब डॉलर का लक्ष्य तय करें। उन्होंने बताया कि देश के 400 अरब डॉलर के निर्यात में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 10 फीसदी है। भारत ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में 400 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य को पार कर लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार संयुक्त अरब अमीरात और अन्य जगह में इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक सूत्रधार और प्रवर्तक के रूप में कार्य करेगी। गौरतलब है कि फरवरी में भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) द्वारा एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए थे, जो एक मई से लागू होगा। उन्होंने कहा ?कि इस समझौते से यूएई, अफ्रीका और पश्चिम एशिया के देशों सहित अन्य क्षेत्रों को निर्यात में बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। यूएई में हमारा निर्यात बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में हम इसे दोगुना या तिगुना करने के लिए काम करेंगे। गोयल ने दुबई में हाल ही में द इंडिया ज्वेलरी एक्पोजिशन (आईजेईएक्स) केंद्र का भी उदघाटन किया।

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी में भी तेजी

- सोना 51,518 रुपए प्रति दस ग्राम, चांदी 67,085 रुपए प्रति किलोग्राम

मुंबई (ईएमएस)। वै?श्विक बाजार में उतार-चढ़ाव की वजह से बुधवार को भारतीय बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। सोने का भाव एक महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया था, जो वापस चढ़ रहा है। एमसीएक्स पर बुधवार को सोने की कीमत 0.45 फीसदी बढ़कर 51,518 रुपए प्रति दस ग्राम पर पहुंच गई है, वहीं चांदी के दाम में 0.21 फीसदी की तेजी आई है। इसके बाद चांदी का भाव उछलकर 67,085 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। वै?श्विक बाजार में भी सोने की कीमत पिछले कुछ सत्र में 2 फीसदी गिरने के बाद 0.1 फीसदी चढ़ गई। सोने का हाजिर भाव बुधवार को 1,920.6 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया। मंगलवार को यह 1.8 फीसदी की बड़ी गिरावट के साथ 28 फरवरी के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था। चांदी की कीमत में भी तेजी आई है। चांदी का हाजिर मूल्य 0.25 फीसदी बढ़त के साथ 24.99 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया।

विशेषज्ञों का कहना है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म होने के बाद पीली धातु की मांग में कमी आएगी और कीमतें और भी नीचे जा सकती हैं। अनुमान है कि अगले 50 दिनों में वै?श्विक बाजार में सोने का हाजिर भाव 1,892 डॉलर प्रति औंस तक जा सकता है। चांदी भी 24 डॉलर प्रति औंस के आसपास रहने का अनुमान है। भारतीय बाजार में चांदी 66,550 रुपए के आसपास ट्रेडिंग करने का अनुमान है, जबकि सोना 50,550 रुपए तक सस्ता हो सकता है। देश भर में सोने के आभूषणों की कीमत उत्पाद शुल्क, राज्य करों और मेकिंग चार्ज के कारण बदलती रहती है।

पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में आठवीं बार बढ़ोतरी

नई दिल्ली (ईएमएस)। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में बुधवार को एक बार फिर 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। पिछले नौ दिनों में कुल 5.60 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियों की तरफ से जारी मूल्य संबंधी अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101.01 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर अब 100.21 रुपए प्रति लीटर और डीज़ल की कीमत 91.47 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 92.27 रुपए प्रति लीटर हो गई है। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है, लेकिन इनके दाम स्थानीय कर के आधार पर अलग-अलग राज्यों में भिन्न हैं। पेट्रोल तथा डीज़ल की कीमतें रिकॉर्ड 137 दिन तक स्थिर रहने के बाद 22 मार्च को बढ़ाई गई थीं। तब से आठवीं बार कीमतों में वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में अब तक कुल 5.60 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है।

पेट्रोल औ- डीजल पर रोड और इन्फ्रा सेस से पिछले दस सालों में 11.32 लाख करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया गया

नई दिल्ली (ईएमएस)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि पेट्रोल औ- डीजल पर रोड और इन्फ्रा सेस से पिछले दस सालों में 11.32 लाख करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया गया है। यह आंकड़ा वर्ष 2010-11 से 2022-23 के बीच की अवधि का है। यानी औसतन हर साल करीब एक लाख करोड़ रुपये सेस से प्राप्त हुआ है। सीतारमण ने ये भी जानकारी दी है कि वर्ष 2013-14 से 2022 के बीच हेल्थ एवं एजुकेशन सेस 3.77 लाख करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया गया, जबकि इसमें उपयोगिता 3.94 लाख करोड़ रुपये की रही है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र की ओर से राज्यों को टैक्स में हिस्सेदारी के तौर पर 8.35 लाख करोड़ रुपये इस वित्तीय वर्ष में दिए गए हैं, जबकि संशोधित अनुमान 7.45 लाख करोड़ रुपये का था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि सरचार्ज और सेस के एवज में कटौती के दावे से संबंधित पिछली तिथि से संशोधन का उद्देश्य इस प्रावधान का दुरुपयोग रोकना है।

यह खासकर उन लोगों के लिये है, जो इसे छूट या कारोबार खर्च के रूप में देखते रहे हैं। वित्त विधेयक में अधिभार या उपकर के लिए कटौती की अनुमति पर रोक आकलन वर्ष 2005-06 से लागू करने का प्रस्ताव रखा गया था। लोकसभा में वित्त विधेयक में संशोधन को दी गई मंजूरी के मुताबिक, उपकर या अधिभार के बदले कटौती के लिए किया गया कोई भी दावा 'कम बताई गई आय' माना जाएगा और वह 50 फीसदी जुर्माने का हकदार होगा। वित्त मंत्री ने लोकसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि करों पर लगने वाले उपकर एवं अधिभार का वर्षों से दुरुपयोग होता आया है और लोग इसे छूट या कारोबारी खर्च के तौर पर लेते रहे हैं।

वित्त मंत्री ने कहा, इस पर लोग अदालतों में भी गए हैं। इसलिए पिछली तारीख से लागू होने वाले प्रभाव के साथ एक संशोधन लाया गया है ताकि अधिक स्पष्टता आए वित्त मंत्री ने इस संशोधन की वजह से करदाताओं पर किसी तरह का बोझ न पड़ने का जिक्र करते हुए कहा कि अगर करदाता खुद ही कटौती के रूप में बताई गई राशि का खुलासा कर अधिकारियों के सामने करते हैं तो उन पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। करदाता की आय का नए सिरे से आकलन किया जाएगा जिसके बाद वैध कर का भुगतान किया जा सकता है। वित्त मंत्री ने वित्त विधेयक में 39 संशोधनों का प्रस्ताव रखा था जिन्हें लोकसभा ने ध्वनि मत से मंजूरी दे दी।

इनमें क्रिप्टो करेंसी पर टैक्सेशन को लेकर नियम सख्त करने से संबंधित संशोधन भी शामिल है। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट ने क्रिप्टो करेंसी से कमाई पर टैक्स की स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है। 1 अप्रैल, 2022 से क्रिप्टोकरेंसी की लेनदेन से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत की दर से आयकर लगने के अलावा उपकर एवं अधिभार भी लगाए जाएंगे। साल भर में 10 हजार रुपये से अधिक डिजिटल मुद्रा के भुगतान पर 1 फीसदी की दर से टीडीएस लगाने का भी प्रस्ताव रखा गया है।

कश्मीरी पंडितों के कातिल बिट्टा पर 31 साल बाद चलेगा मर्डर केस

नई दिल्ली (ईएमएस)। कश्मीरी पंडितों की नृशंस हत्या करने वाले बिट्टा कराटे पर 31 साल बाद केस चलने जा रहा है। बिट्टा कराटे का असली नाम फारूक अहमद डार है। बिट्टा ने खुद स्वीकार किया था कि उसने 1990 में 30 से 40 कश्मीरी पंडितों की हत्या की। अब उसपर हत्या का मुकदमा चलने जा रहा है। बिजनेसमैन सतीश टिकू की हत्या के मामले में परिवार ने फिर से सुनवाई करने की अर्जी श्रीनगर कोर्ट में दी है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सतीश टिकू के परिवार से याचिका की हार्ड कॉपी पेश करने को कहा है। अब इस मामले में 16 अप्रैल को फिर सुनवाई होगी। टिकू के परिवार की तरफ से वकील उत्सव बैंस अपना पक्ष कोर्ट में रख रहे हैं। बता दें कि बिट्टा कराटे ने टेलिविजन पर हत्याओं की बात स्वीकार की है। फारूक अहमद डार का नाम बिट्टा कराटे इसलिए पड़ा क्योंकि वह मार्शल आर्ट में ट्रेंड था। 'द कश्मीर फाइल्स' फिल्म आने के बाद एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार का मुद्दा उभरकर सामने आ गया है। देशभर में कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने की मांग भी तेज हो रही है। लोग इस बात की भी मांग कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार करने वाले आतंकियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। बिट्टा इस समय जमानत पर रिहा है। उसे कश्मीरी निर्दोष लोगों की हत्या के आरोप में जेल में डाला गयता था। 1991 में उसने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि उसने 20 कश्मीरी पंडितों की हत्या की है। इसके बाद उसे सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। उसपर 19 से ज्यादा अधिक उग्रवाद से संबंधित म्मले हैं। वह 16 साल जेल में रहा और इसके बाद टाडा अदालत ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया।

दुबई एक्सपो में हिन्दुस्तान का जलवा, यूएई के दिल में हमेशा के लिए बस गया है भारत

दुबई (ईएमएस)। दुबई एक्सपो में भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर शिरकत कर रहे हैं। दुबई एक्सपो में भारत के कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। इस मौके पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अपने आप को दुनिया में सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित करना चाहता है, भारतीय युवा उद्यमियों में स्टार्टअप की एक प्यास-सी जग चुकी है। केंद्रीय मंत्री गोयल ने दुबई एक्सपो में लगे भारत पवेलियन की कामयाबी पर भारत और दुबई की दोस्ती की तारीफ की। उन्होंने कहा, हमारी दोस्ती दुनिया के कई देशों में ईर्ष्या का मुद्दा बन गई है। इसतरह के देशों को हमारी दिनों दिन मजबूत होती दोस्ती नहीं सुहाती, जबकि सच्चाई ये है कि यूएई ने अपने दिल में भारत को हमेशा के लिए बसा लिया है।

साथ केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुबई को धन्यवाद कहूंगा कि भारत को सम्मान दिवस समारोह शामिल होने का विशेषाधिकार दिया गया। यूएई के सहिष्णुता और सह-अस्तित्व मंत्री और एक्सपो 2020 दुबई के आयुक्त जनरल ने भारत के केंद्रीय मंत्रियों का स्वागत किया। एक्सपो-2020 दुबई में करीब 700 स्टार्टअप ने अपने अनूठे नवाचार को प्रदर्शित किया है। पीयूष गोयल ने स्टार्टअप से अपनी कहानी को दूरदराज के इलाकों, गांवों, छोटे शहरों, पूर्वोत्तर भारत और अन्य क्षेत्रों में भी ले जाने का आग्रह किया।

वहीं शेख नाहयान ने भारत की तारीफ कर कहा कि यहां उन्नत तकनीक, नवीनता, अंतरिक्ष खोज, स्मार्ट शहर सब आकर्षित करते हैं। शेख ने कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों में भारत का नेतृत्व उन्हें खास बनाता है। उन्होंने कहा कि यूएई का भारत के साथ काफी पुराना और गहरा रिश्ता हैं। हम भारत के साथ मिलकर अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने और साधनों को बनाने के लिए उत्सुक हैं।

गोयल ने कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच मुक्त व्यापार समझौते ने बड़े अवसर खोले हैं और दोनों देशों के उद्योगों को द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 250 अरब अमेरिकी डॉलर तक ले जाने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर भारत और यूएई ने फरवरी में हस्ताक्षर किए थे और इसके एक मई से लागू होने की उम्मीद है। गोयल ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के पास निवेश के लिए काफी अधिशेष है जबकि भारत एक बड़ा बाजार और आकर्षक गंतव्य है।

वहीं दुबई में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह एक्सपो में एक साथ नजर आए। जहां वे डांस करते नजर आए। सोशल मीडिया उनके डांस का विडियो खूब शेयर किया गया। वहीं बॉलीवुड की सिंगर कविता कृष्णमूर्ति ने भी अपनी प्रस्तुति दी।

मध्य इजराइल के शहर ब्नेई ब्राक में बाइक सवार बंदूकधारी ने चलाई अंधाधुंध गोलियां, 4 लोगों की मौत

येरुशलम (ईएमएस)। मध्य इजराइल के शहर ब्नेई ब्राक में बाइक पर सवार एक बंदूकधारी ने भीड़-भाड़ वाली जगह पर गोलीबारी की जिसमें चार लोगों की मौत हो गई। हमलावर को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया। गोलीबारी की यह घटना क्यों हुई यह स्पष्ट नहीं है।

मीडिया में आई खबरों में कहा गया है कि हमलावर वेस्ट बैंक का रहने वाला फलस्तीनी था। एक सप्ताह के भीतर हुए तीसरे हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा कि देश अरब आतंकवाद की लहर का सामना कर रहा है। पुलिस ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि बंदूकधारी एक असॉल्ट राइफल लिए हुए और उसने राहगीरों पर गोलीबारी की। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने हमलावर को मार गिराया।

पुतिन को शांति पर सहमत करने में कर सकता है 'सॉफ्ट पावर' का प्रयोग, ईयू नेताओं ने जताई उम्मीद

लंदन (ईएमएस)। यूरोपीय संघ (ईयू) के कुछ नेताओं ने उम्मीद जताई कि रूस-यूक्रेन संघर्ष में बातचीत का रास्ता चुनने के लिए भारत रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को प्रभावित करने को लेकर अपने 'सॉफ्ट पावर' का उपयोग करने में सक्षम हो सकता है। नीदरलैंड के विचार समूह 'द लंदन स्टोरी' द्वारा डिजिटल माध्यम से आयोजित सामूहिक परिचर्चा में स्वीडन से जैकप डलांदे और डेनमार्क से मारग्रेट औकन ने हिस्सा लिया। दोनों यूरोपीय संसद में ग्रीन/यूरोपियन फ्री अलायंस के सदस्य हैं।

'यूरोपीय संघ और रूसी हितों के बीच फंसे यूक्रेन पर भारत का रुख' विषय पर वार्ता में पूर्व भारतीय विदेश सचिव श्याम सरन भी शामिल हुए। जैकप ने कहा उम्मीद है कि यूरोपीय संघ अपने सॉफ्ट पावर का उपयोग लोकतंत्र की ओर भारत के झुकाव को आसान बनाने के लिए कर सकता है और भारत अपने 'सॉफ्ट पावर' का उपयोग पुतिन को यह समझाने के लिए कर सकता है कि एक कदम बातचीत की मेज की ओर कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका है।

उल्लेखनीय है कि सॉफ्ट पॉवर शब्द का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किया जाता है, जिसके तहत कोई देश परोक्ष रूप से सांस्कृतिक या वैचारिक साधनों के माध्यम से किसी अन्य देश के व्यवहार या हितों को प्रभावित करता है। औकन ने भारत के लिए आंतरिक और बाहरी रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों पर खरा उतरने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। पूर्व फ्रांसीसी राजनयिक जैस्मीन जेरिनिनी ने कहा कि हाल के वर्षों में यूरोपीय संघ-भारत संबंधों के लिए सुरक्षा सहयोग कैसे अधिक प्रासंगिक हो गया है।

एक सवाल के जवाब में सरन ने कहा कई समझौते हैं जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संबंध में किए गए हैं, इसलिए संबंधित देशों पर उंगली उठाना बहुत मददगार नहीं है। सरन ने कहा आज के समय में विश्व अर्थव्यवस्था की वैश्वीकृत प्रकृति को स्वीकार करने की आवश्यकता है और देश में हाल की उच्च-स्तरीय यात्राओं का जिक्र करते हुए कहा कि भारत एक सकारात्मक भूमिका निभा सकता है।

बैंगलोर की रोमांचक जीत, कोलकाता को 3 विकेट से हराया

नई दिल्ली । इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन के छठे मुकाबले में रायल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना कोलकाता नाइटराइजर्स से हुआ। बैंगलोर के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टास जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। बैंगलोर की घातक गेंदबाजी के आगे कोलकाता की पूरी टीम महज 128 रन पर सिमट गई। आखिरी ओवर तक चले मुकाबले में बैंगलोर ने 19.2 ओवर में जीत का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। दिनेश कार्तिक ने आखिरी ओवर में एक छक्का और चौका लगाते हुए टीम को जीत दिलाई। यह बैंगलोर की पहली जीत है जबकि कोलकाता की पहली हार । छोटे स्कोर का पीछा करने उतरी बैंगलोर के लिए पारी की शुरुआत कप्तान फाफ डु प्लेसिस के साथ अनुज रावत उतरे। उमेश यादव ने तीसरी ही गेंद पर रावत को शून्य पर विकेट के पीछे कैच करवा वापस भेज दिया। टिम साउदी ने बैंगलोर के कप्तान को 5 रन पर रहाणे के हाथों कैच करवा टीम को बड़ी विकेट दिलवाई। इसके ठीक बाद अगले ओवर की पहली गेंद पर उमेश यादव ने विराट कोहली को 12 रन पर विकेट के पीछे शिकार बनाया।

डेविड विली 18 रन बनाकर सुनील नरेन की गेंद पर नीतीश राणा द्वारा लपके गए। इसके बाद टीम को शाहबाज अहमद ने संभाला और कुछ अच्छे शाट्स लगाए। लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने उनको लालच देकर 27 रन पर स्टंप करवाया। इसके बाद एक और बल्लेबाज रदरफोर्ड जो 28 रन बनाकर जमे हुए थे उनको टीम साउदी ने विकेट के पीछे कैच करवाया। वनिंदु हसरंगा को साउदी ने आंद्रे रसेल के हाथों 4 रन पर कैच करवाया।

पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता के लिए अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर पारी की शुरुआत करने उतरे। 10 रन की छोटी पारी खेलने के बाद आकाश दीप के गेंद पर वेंकटेश अपना विकेट गंवा बैठे। मोम्मद सिराज ने अजिंक्य रहाणे को फंसा और बड़ा शाट खेलते हुए वह 9 रन पर बाउंड्री पर शाहबाज को कैच दे बैठे। नीतीश राणा 10 रन बनाकर दीप की गेंद पर आउट होकर वापस लौटे। कप्तान श्रेयस अय्यर महज 13 रन बनाकर हसारंगा की गेंद पर डु प्लेसिस को कैच दे बैठे।

लगातार विकेट गिरने के बाद सुनील नरेन से टीम को उम्मीद थी लेकिन वह भी हसारंगा की गेंद पर 12 रन बनाने के बाद आकाशदीप को कैच दे बैठे। इसके बाद हसारंगा ने शेल्डन जैक्शन को बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड कर दिया। टीम की उम्मीद सैम बिलिंग्स भी 14 रन बनाकर हर्षल पटेल के शिकार बन गए। 18 गेंद पर 25 रन बनाने के बाद आंद्रे रसेल हर्षल की गेंद पर विकेट के पीछे दिनेश कार्तिक को अपना कैच दे बैठे। हसारंगा ने 4 ओवर में 20 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। आकाश ने 3.5 ओवर में 45 रन देकर 3 विकेट चटकाए। हर्षल ने दो जबकि मोहम्मद सिराज ने 1 बल्लेबाज को आउट किया।

काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई टली, 4 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

प्रयागराज (ईएमएस)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किसी भी वरिष्ठ सरकारी वकील की अनुपस्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर मामले की सुनवाई समय की कमी के चलते चार अप्रैल तक के लिए टाल दी। वाराणसी की अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने कहा, यद्यपि केंद्र और राज्य पक्षकार हैं, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि उनकी ओर से कोई वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित नहीं है।

हालांकि, राज्य की ओर से स्थाई अधिवक्ता राजेश कुमार मिश्रा और वेद प्रकाश द्विवेदी उपस्थित थे। इससे पूर्व 24 मार्च को मंदिर की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने दलील दी थी कि पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र वैसा ही है, जैसा 15 अगस्त, 1947 को था। इसलिए पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के प्रावधान यहां लागू नहीं किए जा सकते। पूजा स्थल अधिनियम की धारा 4 के तहत 15 अगस्त, 1947 को मौजूद किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र के परिवर्तन के संबंध में किसी भी तरह के मुकदमे या किसी अन्य कानूनी कार्यवाही की अनुमति नहीं है।

भारत के साथ समुद्री सुरक्षा समझौतों से श्रीलंका को कोई खतरा नहीं

कोलंबो (ईएमएस)। श्रीलंकाई सरकार ने कहा है कि भारत के साथ हाल में जिन समुद्री सुरक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, उन समझौतों से द्वीपीय देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। देश के कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा गलत व्याख्या की जा रही है। इस सप्ताह यहां भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के दौरे के दौरान 'समुद्री बचाव समन्वय केंद्र' (एमआरसीसी) की स्थापना को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, एमआरसीसी की स्थापना, क्षेत्र में संचालित हो रहे पोतों के संकट में पड़ने पर उनकी तलाश और बचाव के लिए बेहद अहम है। इससे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रस्तावों के अनुपालन के साथ पोतों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। बयान में कहा गया कि श्रीलंका के तलाशी एवं बचाव (एसएआर) क्षेत्र में वाणिज्यिक पोतों के समुद्री एसएआर परिचालन के लिए श्रीलंकाई नौसेना उत्तरदायी है। बयान में भारत की ओर से मुफ्त में 'फ्लोटिंग डॉक' सुविधा प्राप्त होने का भी उल्लेख किया गया। बयान के अनुसार भारत ने श्रीलंका को बिना किसी शुल्क के एक डोर्नियर निगरानी विमान उपलब्ध कराने को भी कहा है। बयान में कहा गया कि भारत सरकार के साथ सुरक्षा समझौतों से श्रीलंका की राष्ट्रीय सुरक्षा को न कोई खतरा है और न ही कोई रुकावट पैदा होगी जैसा कि कई प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दुष्प्रचार किया जा रहा है।

खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा आंतकी हमला, छह सुरक्षाकर्मी मारे गए और 22 अन्य घायल

पेशावर (ईएमएस)। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में किले के अंदर स्थित सुरक्षा मुख्यालय पर आतंकवादी हमले में कम से कम छह सुरक्षाकर्मी मारे गए और 22 अन्य घायल हो गए। जिला पुलिस अधिकारी वकार अहमद खान ने बताया कि आतंकवादियों ने दक्षिण वजीरिस्तान की सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के टैंक जिले में एफसी लाइन पर हमला किया गया।

मुठभेड़ में तीन हमलावर भी मारे गए। अधिकारी ने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि टैंक जिले की ओर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है और हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में तलाश अभियान चलाया जा रहा है।

यूक्रेन जंग से सबक, ताइवान पर चार साल तक हमला नहीं करेगा चीन

बीजिंग (ईएमएस)। यूक्रेन में रूसी आक्रमण के बाद चीन ने ताइवान पर किसी भी संभावित आक्रमण को कम से कम चार साल के लिए टाल दिया है। खुफिया सूत्रों ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब स्व-शासित द्वीप ताइवान पर कोई भी कदम उठाने से पहले पुतिन की 'विफलताओं का विश्लेषण करने वाले हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, पूर्वी एशियाई महाशक्ति चीन ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन के शेष कार्यकाल के लिए हमला नहीं करेगा। त्साई इंग-वेन का कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा। बीजिंग के लिए यूक्रेन का सबक यह है कि वह आसानी से युद्ध नहीं छेड़ेगा। उन्होंने कहा कि चीन यूक्रेन में रूस की कमियों का अध्ययन कर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में सुधार करेगा। अगर यह युद्ध कभी शुरू करेगा, तब यह बड़े स्तर पर होगा, और ताइवान को संभावनाओं के व्यापक दायरे के साथ बीजिंग के इरादों का आकलन करना चाहिए। ताइवान द्वारा रक्षा ताकत बढ़ाने का जिक्र करते हुए कहा, हम भी यहां निष्क्रिय होकर इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम खाली नहीं बैठे हैं।' चीनी हमले की आशंका वर्षों से चल रही है।

चीन लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं का विस्तार कर रहा है और दक्षिण चीन सागर में सैन्य अभ्यास और कथित 'भूमि हड़पने' सहित अमेरिका के वैश्विक आधिपत्य को तेजी से चुनौती दे रहा है। माना जाता है कि हाल के वर्षों में शिनजियांग प्रांत के रेगिस्तान में लगभग 800 वर्ग किमी में फैले एक साइलो कॉम्प्लेक्स के निर्माण के बाद उसके परमाणु शस्त्रागार में वृद्धि हुई है।

हाल ही में, यह सामने आया कि चीन देश भर में उसके परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम एक उच्च गति वाली 'मिसाइल ट्रेन' की तलाश कर रहा है, जिससे उन्हें (परमाणु हथियारों को) ट्रैक करना और नष्ट करना कठिन हो गया। यूक्रेन के आक्रमण के

मुख्यमंत्री की उपस्थिति में बीएसई में सूचीबद्ध हुआ वडोदरा मनपा का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड-2022

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि महानगरों और शहरों में रहने वाले नागरिकों की सुख-सुविधा, अवसंरचना विकास के कार्यों और शहरी अवसंरचना सुविधाओं के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिए पूंजी जुटाकर गुजरात की महानगर पालिकाओं ने स्थानीय शहरी निकायों को वैश्विक वित्तीय बाजारों के साथ जोड़ने की सफलता हासिल की है।

वे बुधवार को मुंबई में राज्य की वडोदरा महानगर पालिका (वीएमसी) के पहले म्युनिसिपल बॉन्ड-2022 के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध होने के अवसर पर आयोजित समारोह में बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर के सूचीबद्ध होने के अवसर पर शेयर बाजार में पारंपरिक घंटा बजाकर दिन भर के कामकाज का आरंभ कराया।

वडोदरा महानगर पालिका ने केंद्र सरकार की 'अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन' (अमृत) योजना के अंतर्गत देय अंशदान की 100 करोड़ रुपए की रकम म्युनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से जुटाने में सफलता प्राप्त की है।

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन के लिए गत 24 मार्च को यह बॉन्ड इश्यू खोला गया था। यह इश्यू खुलते ही पहले ही सेकंड में 4.52 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इतना ही नहीं, इश्यू का समय पूरा होने तक महानगर पालिका के 100 करोड़ रुपए के बॉन्ड के समक्ष 36 निवेशकों की ओर से 10.07 गुना ज्यादा यानी कि 1007 करोड़ रुपए की बोलियां मिली थी।

वडोदरा महानगर पालिका का यह बॉन्ड आज तक की सबसे कम यानी कि 7.15 फीसदी की दर पर सब्सक्राइब हुआ है, यह भी एक उपलब्धि है।

मुख्यमंत्री ने वडोदरा महानगर पालिका के इस पहले म्युनिसिपल बॉन्ड के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के अवसर पर महानगर सेवा सदन की पूरी टीम और महापौर श्री केयूर रोकड़िया एवं मनपा आयुक्त श्रीमती शालीनि अग्रवाल को बधाई दी।

वडोदरा महानगर पालिका बॉन्ड के जरिए जुटाई गई 100 करोड़ रुपए की रकम को सिंघरोट जलापूर्ति परियोजना तथा अमित नगर में एपीएस के अंतर्गत खर्च करेगा। सिंघरोट में जलापूर्ति की परियोजना के जरिए शहरी नागरिकों की पेयजल जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। वहीं, अमित नगर एपीएस प्रोजेक्ट सीवेज के पानी के सुव्यवस्थित निस्तारण में सहायक सिद्ध होगा।

श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के शहरी स्थानीय निकायों, शहरी विकास विभाग और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के सहयोग से म्युनिसिपल बॉन्ड जारी कर स्थानीय स्वशासन निकायों को विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन की प्रेरणा दी है।

उन्होंने आगे कहा कि बॉन्ड के जरिए जुटाई गई ऐसी पूंजी से शहरी बुनियादी ढांचा के कार्यों की वृद्धि के साथ जन सहभागिता को भी जोड़कर उन्होंने 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' की मंशा को साकार किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात में अहमदाबाद और सूरत महानगर के बाद वडोदरा तीसरी ऐसी महानगर पालिका है जिसने ऐसे बॉन्ड के माध्यम से शहरी कल्याण के कार्यों को नई दिशा दी है।

पाटीदार नेता नरेश पटेल कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल, जयपुर में प्रशांत किशोर के साथ मुलाकात

अहमदाबाद (ईएमएस) पाटीदारों के आस्था का केन्द्र खोडलधाम ट्रस्ट के प्रमुख नरेश पटेल का कांग्रेस में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है नरेश पटेल की आज राजस्थान के जयपुर में प्रशांत किशोर के साथ मुलाकात के बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि जल्द ही कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं गुजरात में काफी समय से दो बातों को लेकर चर्चा चल रही हैं, पहली राज्य विधानसभा के चुनाव समय से पहले हो सकते हैं क्या? और दूसरी खोडलधाम के प्रमुख और पाटीदार नेता नरेश पटेल राजनीति में आएंगे या नहीं? अगर शामिल होते हैं किस राजनीतिक दल में जाएंगे? इन अटकलों के बीच नरेश पटेल के कांग्रेस में शामिल होने की बड़ी खबर सामने आई है बताया जा रहा है कि नरेश पटेल और प्रशांत किशोर के बीच आज जयपुर में एक अहम बैठक हुई है बता दें कि हाल ही में नरेश पटेल ने अप्रैल महीने के मध्य में राजनीति में शामिल होने पर फैसला करेंगे अब उनके कांग्रेस में शामिल होने की खबर सामने आई है जानकारी है कि फिलहाल नरेश पटेल कांग्रेस संगठन में काम करेंगे पहले चर्चा थी कि नरेश पटेल गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे परंतु कांग्रेस सूत्रों ने इस बात को खारिज कर दिया है फिलहाल नरेश पटेल कांग्रेस संगठन के लिए काम करेंगे हांलाकि इस संदर्भ में कांग्रेस की ओर से कोई अधिकृत घोषणा नहीं की गई है बताया जाता है कि जयपुर में नरेश पटेल और प्रशांत किशोर के बीच हुई बैठक की मध्यस्थता राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी नरेश पटेल और प्रशांत किशोर के बीच यह पहली बैठक नहीं है, इससे पहले भी दोनों की मुलाकात हो चुकी है और नरेश पटेल ने इस बात को स्वीकार भी किया है देखना होगा कि नरेश पटेल कांग्रेस में कब शामिल होते हैं और उनके साथ आने से कांग्रेस को आगामी चुनाव में कितना फायदा होता है नरेश पटेल का साथ मिलने से कांग्रेस को फायदा और भाजपा की चुनौतियां बढ़ जाएंगी वैसे पाटीदार आंदोलन के बावजूद वर्ष 2017 में भाजपा गुजरात में सरकार बनाने में सफल रही थी नरेश पटेल के कांग्रेस में शामिल होने से पाटीदार वोटरों पर कितना असर होता है तो आगामी चुनावों के बाद ही पता चलेगा

पीएम मोदी आगामी 21 अप्रैल को आएंगे गुजरात, दाहोद से करेंगे चुनावी शंखनाद

अहमदाबाद (ईएमएस) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फिर एक बार गुजरात आ रहे हैं मार्च के बाद पीएम मोदी अप्रैल महीने में दो दिवसीय दौरे पर गुजरात आएंगे 21 अप्रैल को पीएम मोदी दाहोद से विधानसभा चुनावों के लिए शंखनाद करेंगे गुजरात दौरे के दूसरे दिन 22 अप्रैल को पीएम मोदी बनासकांठा में पशुपालक महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम मोदी के गुजरात दौरे को लेकर प्रदेश भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं बता दें कि गुजरात विधानसभा के इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं और उसे लेकर भाजपा पहले से तैयारियों में जुटी हैं ऐसे में पीएम मोदी 21 अप्रैल को दो दिवसीय गुजरात दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान वे दो विराट जनसभाओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी 21 अप्रैल को दाहोद से आदिवासी सम्मेलन में विधानसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे इस सम्मेलन में 5 लाख से ज्यादा आदिवासी एकत्र हो ऐसा आयोजन करने के लिए गुजरात प्रदेश प्रमुख सीआर पाटील की अध्यक्षता में एक बैठक भी हो चुकी है गुजरात में आदिवासियों का वोट विधानसभा चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं इसलिए अन्य समाज की भांति आदिवासी समाज को आकृष्ट करने के लिए पीएम मोदी की उपस्थिति में दाहोद में आदिवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया है अंबाजी से उमरगाम तक 27 विधानसभा सीटों पर आदिवासी समाज का प्रभुत्व है ऐसे में प्रधानमंत्री का दाहोद दौरा अहम है गुजरात यात्रा के दूसरे दिन पीएम मोदी उत्तरी गुजरात के बनासकांठा में महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे 22 अप्रैल को बनासकांठा में पशु पालक महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है जिसमें पीएम मोदी आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बात करेंगे गुजरात के दो दिवसीय दौरे के दौरान पीएम मोदी अलग अलग अलग जिलों में विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे पीएम मोदी के दाहोद के आदिवासी सम्मेलन को भव्यातिभव्य बनाने का प्रदेश भाजपा प्रमुख सीआर पाटील ने दाहोद, छोटाउदेपुर, महीसागर, पंचमहल और वडोदरा जिले कार्यकर्ताओं को आदेश दिया है गौरतलब आदिवासी इलाकों में पिछले काफी समय से पार-तापी-नर्मदा रिवर लिंक अप योजना को लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है ऐसे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का दाहोद का दौरा महत्वपूर्ण होगा पीएम मोदी दाहोद में करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे पीएम मोदी का दाहोद दौरा आगामी गुजरात चुनावों की दिशा तय करेगा

एक ही परिवार की चार लोगों की हत्या, घर का मुखिया फरार

अहमदाबाद (ईएमएस) शहर के पूर्वी क्षेत्र की एक सोसायटी में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई परिवार का मुखिया फरार है आशंका है कि परिवार के मुखिया ही पत्नी, दो संतान और दादी की हत्या कर फरार हो गया है फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है जानकारी के मुताबिक पूर्वी अहमदाबाद के विराटनगर क्षेत्र की दिव्यप्रभा सोसायटी के मकान नंबर 30 में सोनल मराठी अपने पति विनोद, पुत्र गणेश, पुत्री प्रगति और दादी सुभद्रा मराठी के साथ रहती थी पिछले चार दिनों से सोनल अपनी मां अंबाबेन का फोन नहीं उठा रही थी कुछ अनहोनी की आशंका के चलते अंबाबेन ने पुलिस कंट्रोल से संपर्क किया जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई सोनल मराठी के मकान का दरवाजा बंद था और भीतर से तीव्र दुर्गंध आ रही थी पुलिस घर के भीतर घुसी तो अंदर का नजारा देख चौंक उठी मकान के अलग अलग कमरों में सोनल मराठी, सुभद्रा मराठी, गणेश और प्रगति की लाशें पड़ी हुई थी चार लोगों की हत्या की खबर के बाद पुलिस के आला अफसर भी घटनास्थल पर पहुंच गए और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी पुलिस के मुताबिक परिवार का मुखिया विनोद मराठी लापता है आशंका है कि विनोद ही किन्हीं कारणों से पत्नी, बेटी-बेटे और दादी की हत्या की और फरार हो गया है फिलहाल तो पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज एकत्र कर मामले की जांच शुरू की है

कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के दौरान मधुमक्खियों का हमला, विद्यार्थियों में मची अफरा तफरी

भावनगर (ईएमएस) गुजरात में सोमवार से कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए सुबह और कक्षा 12 के विद्यार्थियों की दोपहर को परीक्षा ली जाती है दो विषयों की परीक्षाएं शांतिपूर्ण माहौल में खत्म हो चुकी हैं और कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई लेकिन आज सुबह भावनगर के तलाजा के एक परीक्षा केन्द्र में उस वक्त अफरातफरी मच गई जब मधुमक्खियों के झुंड ने स्कूल के कमरे में धावा बोल दिया मधुमक्खियों के हमले से शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों में अफरातफर मच गई घटना भावनगर जिले की तलाजा तहसील के शथरा गांव की एक स्कूल की है इस घटना में परीक्षा दे रहे कक्षा 10 के 10 भी ज्यादा विद्यार्थी मधुमक्खियों के डंग से जख्मी हो गए कुछ समय के लिए परीक्षा को रोक दिया गया और एम्ब्युलैंस 108 बुलाकर जख्मी विद्यार्थियों को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भेजा गया कुछ देर आतंक मचाने के बाद मधुमक्खियों के झुंड के रवाना होने से स्कूल संचालक और विद्यार्थियों ने राहत की सांस ली

शराब तस्करी के आरोप में राजस्थान रोडवेज की बस का ड्राइवर गिरफ्तार

अहमदाबाद (ईएमएस) शहर की पालडी पुलिस ने राजस्थान राज्य परिवहन निगम के बस ड्राइवर को शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है पुलिस ने ड्राइवर के पास से विदेशी शराब की 52 जितनी बोतलें भी बरामद की हैं गुजरात में संपूर्ण शराबबंदी होने के बावजूद आए दिन शराब पकड़ी जाती है पुलिस से बचने के लिए माफिया नए नए तरीके अपनाते हैं और कुछ समय तक उसमें सफल भी होते हैं, परंतु एक न दिन आखिर धरे जाते हैं ऐसी ही एक घटना में अहमदाबाद की पालडी पुलिस ने राजस्थान राज्य परिवहन निगम की बस के ड्राइवर को दबोच गिरफ्तार कर लिया पालडी पुलिस को सूचना मिली थी कि राजस्थान राज्य परिवहन निगम की बस का ड्राइवर शराब की खेप लगाता है सूचना के आधार पर राजस्थान की बस के पालडी पहुंचने पुलिस ने उसमें जांच की जिसमें अलग अलग विदेशी ब्रांड की 52 जितनी बोतलें बरामद हुई जिसके बाद पुलिस ने बस के ड्राइवर भंवरसिंह शेखावत को गिरफ्तार कर लिया पूछताछ में पता चला कि वह अब तक 10 खेप लगा चुका है ड्राइवर को मूल काम राजस्थान के यात्रियों को उनकी मंझिल तक पहुंचाना था, लेकिन शोर्टकट में रुपए कमाने की लालच में भंवरसिंह ने शराब तस्करी शुरू कर दी पिछले 4-5 महीनों से भंवरसिंह शराब तस्करी कर रहा था प्रत्येक डिलीवरी पर भंवरसिंह को 2000 रुपए मिलते थे भंवरसिंह का काम राजस्थान के जोधपुर से विदेशी शराब लेकर अहमदाबाद के किरण मेवाडा को पहुंचाना था जांच में पता चला कि किरण मेवाडा की राजस्थान में शराब की दुकान है, फिलहाल वह फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है

किसानों को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति के लिए 'सरदार कृषि ज्योति योजना' : मुकेश पटेल

अहमदाबाद (ईएमएस) राज्यों के किसानों को सिंचाई के लिए गुणवत्तायुक्त लगातार बिजली आपूर्ति मुहैया कराने के लिए गुजरात सरकार ने 'सरदार कृषि ज्योति योजना' का अमलीकरण किया है इस योजना के अंतर्गत राजकोट जिले में 31 दिसंबर 2021 तक पिछले 2 साल में रु. 1215.20 लाख के खर्च से जर्जरित बिजली तारों को बदलकर उसका नवीनीकरण किया गया है गोंडल से विधायक गीताबा जाडेजा के प्रश्न के उत्तर में ऊर्जा राज्यमंत्री मुकेश पटेल ने यह जानकारी दी मुकेश पटेल ने बताया कि सरदार कृषि योजना में 80 प्रतिशत रकम राज्य सरकार और 20 प्रतिशत रकम बिजली कंपनी द्वारा दी जाती है इस योजना के अंतर्गत जर्जरित तार, खंभे, फीडर समेत खराब हो चुके बिजली साधनों को बदला जाता है, ताकि लगातार बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराई जा सके

नागरिकों और किसानों को लगातार बिजली आपूर्ति मुहैया कराने को सरकार प्रतिबद्ध : ऊर्जा मंत्री

अहमदाबाद (ईएमएस) ऊर्जा राज्य मंत्री मुकेश पटेल ने आज कहा कि नागरिकों और किसानों को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति लगातार मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार ने ठोस आयोजन किया है जिसमें खेतीवाडी अर्बन और ज्योर्तिग्राम योजना के अंतर्गत फीडरों समेत बिजली लाइनों के जरिए बिजली आपूर्ति की जा रही है राज्य विधानसभा में आज गांधीनगर और सुरेन्द्रनगर जिले में मौजूदा बिजली फीडरों के विभाजन के संदर्भ में प्रश्न के उत्तर में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पिछले दो साल में इन दोनों जिलों में 128 फिडरों का विभाजन किया गया है और इस पर 1832.08 लाख रुपए खर्च किए गए हैं ऊर्जा मंत्री ने कहा कि गांधीनगर जिले में 73 जितने मौजूदा फीडरों का रु. 1330.64 लाख के खर्च से और सुरेन्द्रनगर जिले में 50 फीडरों का रु. 501.44 लाख के खर्च से विभाजन किया गया है गांधीनगर जिले में 172 किलोमीटर की और सुरेन्द्रनगर जिले में 120.55 किलोमीटर की नई बिजली लाइनें डाली गई हैं

बोर्ड की परीक्षाओं में और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना

विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए जाए इसके पहले ही मौत हुई

अहमदाबाद, ३० मार्च ।

फिलहाल गुजरात में कक्षा-१० और १२ की बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है। अब नवसारी में परीक्षा देने के लिए जाए इसके पहले ही एक विद्यार्थी की मौत हुई थी और अस्पताल भेजे जाने पर इसे मृतक घोषित किया गया । प्राप्त जानकारी के अनुसार कक्षा-१२ कॉमर्स की विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए जाए इसके पहले ही इसे अचानक छाती में दर्द होने पर इसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया । हालांकि, उपचार के दौरान विद्यार्थिनी की मौत हुई थी । यह घटना की जानकारी मिलने पर जिला कलेक्टर, जिला शिक्षाधिकारी भी अस्पताल पहुंचे ।

उल्लेखनीय है कि, अहमदाबाद में भी एक परीक्षा के पहले दिन ही एक विद्यार्थी को खेंच आने से मौत हुई थी । मिली जानकारी के अनुसार आशानगर में रहता उत्सव नाम का विद्यार्थी शहर की विद्याकुंज स्कूल में कक्षा-१२ कॉमर्स में पढ़ाई करता था । मंगलवार को यह अकाउंट का पेपर देने के लिए उत्सव कॉलेज में जाने वाला था । हालांकि, परीक्षा पहले ही इसे दोपहर में १ बजे छाती में दर्द होने पर परिवार को जानकारी दी गई थी । जिसकी वजह से उत्सव को तुरंत रेलवे स्टेशन निकट की निजी अस्पताल ले जाया गया । जहां छोटी इलाज के दौरान इसकी मौत हुई थी । यह घटना की जानकारी मिलने पर नवसारी जिला इंचार्ज जिला शिक्षाधिकारी राजेश्री टंडेल और जिला कलेक्टर अमित प्रकाश यादव भी अस्पताल पहुंच गये । अधिकारियों ने घटना की जानकारी लेकर परिजनों को सांत्वना दी । उत्सव की मौत होने पर देर शाम को इसकी अंतिमयात्रा निकाली गई थी, जिसमें समाज के सीनियर, दोस्तों सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए । मीडिया रिपोर्ट के अनुसार परिवार ने एक बेटे का नेत्रदान किए जाने की जानकारी मिली है ।

राज्य में कोरोना के 9 नए मामले, पांच महानगर और 30 जिले में कोई नया मरीज नहीं

अहमदाबाद (ईएमएस) बुधवार को राज्य के तीन कॉर्पोरेशन और दो जिलों में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए हैं राज्य के 5 महानगर और 30 जिलों में कोरोना का एक भी केस पिछले 24 घंटों में दर्ज नहीं हुआ दूसरी ओर 37 लोगों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने का दर 99.10 प्रतिशत पर पहुंच गया है दूसरी और टीकाकरण अभियान के तहत आज 83154 लोगों की कोविड वैक्सीन दी गई स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में अहमदाबाद कॉर्पोरेशन में 4, वडोदरा कॉर्पोरेशन में 2, आणंद, गांधीनगर कॉर्पोरेशन और कच्छ में 1-1 समेत राज्यभर में कोरोना के केवल 9 नए मरीज सामने आए हैं जबकि अहमदाबाद, अमरेली, अरवल्ली, बनासकांठा, भरुच, भावनगर, बोटाद, छोटाउदेपुर, डांग, देवभूमि द्वारका, गांधीनगर, गिर सोमनाथ, जामनगर, जूनागढ़, खेडा, महीसागर, मेहसाणा, मोरबी, नर्मदा, नवसारी, पंचमहल, पाटन, पोरबंदर, राजकोट, साबरकांठा, सूरत, सुरेन्द्रनगर, तापी, वडोदरा और वलसाड समेत 30 जिले और भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, राजकोट और सूरत समेत 5 कॉर्पोरेशन में कोरोना का एक भी मामला पिछले 24 घंटों में सामने नहीं आया राज्य में फिलहाल कोरोना के 122 एक्टिव मामलों में 121 स्टेबल हैं और 1 मरीज वेन्टीलेटर पर है 1212829 लोग अब तक कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 10942 मरीजों की मौत हो चुकी है दूसरी टीकाकरण अभियान के तहत बुधवार को राज्य में 83154 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया जिसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के 2414 को पहला और 19807 को दूसरा टीका लगाया गया 15 से 18 वर्षीय 1168 किशोरों को पहली और 7049 को कोविड की दूसरी वैक्सीन लगाई गई 12 से 15 वर्षीय आयु के 37670 किशोरों को कोरोना का पहला टीका लगाया गया जबकि 15046 नागरिकों को बूस्टर डोज दिया गया राज्य में अब तक 10 करोड़ 60 लाख 91 हजार 036 नागरिकों को वैक्सीनेट किया जा चुका है

गुजरात कांग्रेस को अशोक गहलोत भी दुर्गती से नहीं बचा पाएंगे : सतीश पुनिया

अहमदाबाद (ईएमएस) गुजरात विधानसभा के चुनावों को लेकर राज्य में भाजपा और कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं आज नरेश पटेल के कांग्रेस में शामिल होने की खबरों के बीच गुजरात आए राजस्थान भाजपा के प्रमुख सतीश पुनिया ने बड़ा दावा किया है सतीश पुनिया ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात कांग्रेस को दुर्गती से नहीं बचा पाएंगे गुजरात और राजस्थान कांग्रेस पर प्रहार करते हुए पुनिया ने कहा कि कांग्रेस गुजरात ही पूरे देश में काफी कमजोर हो चुकी है अशोक गहलोत चाहकर भी कांग्रेस को संजीवनी नहीं दे पाएंगे प्रशांत किशोर के गुजरात कांग्रेस के लिए काम करने के बारे में सतीश पुनिया ने कहा कि वह कांग्रेस के लिए विशेषज्ञ जरूर बन सकते हैं लेकिन जब गुजरात में कांग्रेस का जनाधार ही खत्म हो चुका है, ऐसे में प्रशांत किशोर वोट कहां से लाएंगे उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में कांग्रेस की ऐसी दुर्गती होगी जो अब तक कभी नहीं हुई प्रशांत किशोर चाहे कितना प्रयास कर लें, कांग्रेस को दोबारा खड़ी नहीं कर पाएंगे सतीश पुनिया ने कहा कि वर्ष 2022 में गुजरात, 2023 में राजस्थान और वर्ष 2024 में फिर एक भारत हिन्दुस्तान जीतेंगे राजस्थान चुनाव वसुंधरा राजे के चेहरे पर लड़े जाने के सवाल पर पुनिया ने कहा कि हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं हमारी कोशिश है कि 2023 में कांग्रेस को परास्त कर राजस्थान में सरकार बनाएं उन्होंने कहा कि जनसंघ के दौरान 3 प्रतिशत वोट मिलते थे, आज लोकसभा में भाजपा की 303 सीटें हैं अब कांग्रेस केवल राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता में हैं उत्तर प्रदेश में गुजरात कांग्रेस के लोगों ने भी पूरी ताकत लगाई लेकिन सफलता नहीं मिली राजस्थान के लोग जमीन पर मजबूत हैं हम एक-दूसरे से सीखते हैं और मदद करते हैं हमारे लोग बनासकांठा आते हैं और यहां के लोगों की मदद करते हैं 2023 में यही अनुभव राजस्थान में काम आएगा हमारी सरकार में राम मंदिर, धारा 370 जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं

सैमसग ने गैलेक्सी ए सीरीज़ को मजबूत किया; भारत में पाँच नए स्मार्टफोंस का अनावरण किया

फ्लैगशिप 108 मेगापिक्सल ओआईएस कैमरा के साथ गैलेक्सी ए73 5जी की घोषणा की

नई गैलेक्सी ए सीरीज़ में स्लीक एवं ट्रेंडी डिज़ाईन और फ्लैगशिप विशेषताएं हैं, जिनमें ओआईएस कैमरा, आईपी67 रेटेड डयूरेबिलिटी, शक्तिशाली परफॉर्मेंस एवं अनेक ईकोसिस्टम प्रस्तुतियां हैं

Ahmedabad, March, 2022: भारत के सबसे भरोसेमंद स्मार्टफोन ब्रांड, सैमसंग ने आज अपने पोर्टफोलियो में पाँच नए मॉडल **(Gala²y A13/A23/A33 5G/ A53 5G/A73 5G)** शामिल किए। इसके साथ गैलेक्सी ए सीरीज़ स्टाईलिश और टिकाऊ डिज़ाईन, ताजगीभरे नए रंग और फ्लैगशिप

विशेषताओं के साथ और ज्यादा मजबूत हो गई है। इन स्मार्टफोन का उद्देश्य किफायती मूल्य में गैलेक्सी के लेटेस्ट इनोवेशन का एक संपूर्ण पैकेज प्रदान करना है, ताकि शानदार टेक्नॉलॉजी सभी को मिल सके।

गैलेक्सी ए73 5जी में ऑप्टिकल इमेज स्टेब्लाईज़ेशन (ओआईएस) के साथ फ्लैगशिप लेवल का 108 मेगापिक्सल कैमरा, वाटर एवं डस्ट रेज़िस्टैंस के लिए आईपी67रेटिंग के साथ बेहतर डयूरेबिलिटी, शक्तिशाली स्नैपड्रैगन 778 5जी प्रोसेसर और 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ सुपर एमोलेड+ डिस्प्ले है।

सैमसंग इंडिया में श्री आदित्य बाबर, सीनियरडायरेक्टरऔरहेडमार्केटिंगने कहा, ''सैमसंग में हम गैलेक्सी अनुभव के साथ खुलेपन और असीमित संभावनाओं में यकीन करते हैं। गैलेक्सी ए सीरीज़ किफायती मूल्य में फ्लैगशिप जैसी विशेषताएं प्रस्तुत करके इसी विश्वास को प्रतिबिंबित करती है। हम जो पाँच नए मॉडल लॉन्च कर रहे हैं, वो उपभोक्ताओं को स्टाईल, पॉवर एवं उपयोगिता द्वारा प्रेरित करने के लिए तैयार किए गए हैं।

पश्चिम रेलवे द्वारा अहमदाबाद मंडल की 5 जोड़ी ट्रेनों में जोड़े जाएंगे अतिरिक्त कोच

अहमदाबाद ,पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की मांग एवं सुविधा के लिए अहमदाबाद मण्डल से चलने वाली 5 जोड़ी ट्रेनों में अस्थाई तौर पर अतिरिक्त को जोड़े जाएंगे। इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. ट्रेन संख्या 19165/19166 अहमदाबाद-दरभंगा-अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से दिनांक 1 अप्रैल 2022 से 29 मई 2022 तक तथा दरभंगा से 4 अप्रैल 2022 से 1 जून 2022 तक एक सेकंड एसी का कोच अतिरिक्त जोड़ा जाएगा।

2. ट्रेन संख्या 19167/19168 अहमदाबाद-वाराणसी-अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से 2 अप्रैल 2022 से 31 मई 2022 तक तथा वाराणसी से 5 अप्रैल 2022 से 3 जून 2022 तक एक सेकंड एसी का कोच अतिरिक्त जोड़ा जाएगा।

3. ट्रेन संख्या 22956/22955 भुज-बांद्रा टर्मिनस-भुज कच्छ एक्सप्रेस ट्रेन में भुज से 1 अप्रैल 2022 से 31 मई 2022 तक तथा बांद्रा टर्मिनस से 2 अप्रैल 2022 से 1 जून 2022 तक एक थर्ड एसी कोच अतिरिक्त जोड़ा जाएगा।

4. ट्रेन संख्या 20947/20948 अहमदाबाद-एकता नगर-अहमदाबाद जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से 1 अप्रैल 2022 से 31 मई 2022 तक तथा एकता नगर से 1 अप्रैल 2022 से 31 मई 2022 तक के दो एसी चेयर कार कोच अतिरिक्त जोडे जाएंगे।

5. ट्रेन संख्या 22903/22904 बांद्रा छ्लुलृच्द्रब्ॅङ्कङ्ग-ञ्छह्लद्रलृछ टर्मिनस एक्सप्रेस ट्रेन में बांद्रा टर्मिनस से 3 अप्रैल 2022 से 29 मई 2022 तक तथा भुज से 4 अप्रैल 2022 से 30 मई 2022 तक एक थर्ड एसी कोच अतिरिक्त जोड़ा जाएगा।

14 अप्रैल से भावनगर-बांद्रा के बीच चलेगी साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन

अहमदाबाद (ईएमएस) गर्मी की छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में होने वाली भीड़ को ध्यान में रखकर यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा भावनगर टर्मिनस एवं बान्द्रा टर्मिनस के बीच ''साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन'' चलाने का निर्णय लिया गया है। यह स्पेशल ट्रेन विशेष किराये के साथ कुल 14 ट्रिप चलेगी। इस ट्रेन के जनरल कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए अनारक्षित टिकट जारी किया जाएगा। गाड़ी संख्या 09454 (भावनगर-बान्द्रा साप्ताहिक स्पेशल) भावनगर टर्मिनस स्टेशन से 14 अप्रैल, 2022 से 26 मई, 2022 तक प्रत्येक गुरूवार को दोपहर 14.50 बजे चलेगी तथा यह ट्रेन अगले दिन प्रातः 06.00 बजे बान्द्रा टर्मिनस पहुंचेगी। इसी प्रकार, गाड़ी संख्या 09453 (बान्द्रा-भावनगर साप्ताहिक स्पेशल) बान्द्रा टर्मिनस स्टेशन से 15 अप्रैल, 2022 से 27 मई, 2022 तक प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 09.00 बजे चलेगी तथा यह ट्रेन उसी दिन 23.45 बजे भावनगर टर्मिनस पहुंचेगी। इस स्पेशल ट्रेन में सेकन्ड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर एवं जनरल कोच शामिल होंगे। यह ट्रेन अपनी यात्रा के दौरान भावनगर परा, सोनगढ़, धोला, बोटाद, सुरेन्द्रनगर गेट, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, वापी एवं बोरीवली स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में रूकेगी। उपरोक्त स्पेशल ट्रेन के लिए टिकटों की बुकिंग नामित पीआरएस काउंटर एवं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर 01 अप्रैल, 2022 से शुरू होगी। यात्री इस ट्रेन के परिचालन समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए ै.हर्ल्ङ्कॅ्रर्ईहैंगतुदन्ग्ह पर भी जाकर अवलोकन कर सकते हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें।

आदिवासी महिलाओं और युवाओं के कल्याण के लिए काम कर रही रमीलाबेन गामित को पद्मश्री

रमीलाबेन बीजेपी के ट्राइबल फ्रंट के प्रेरणा स्त्रोत, गांधीनगर महानगर अध्यक्ष आरती कालूभाई भील

अहमदाबाद, 30 मार्च, 2022: केंद्र सरकार ने हाल ही में गुजरात के भीतरी इलाकों में रहने वाली आदिवासी महिलाओं के आर्थिक उत्थान और बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालने के लिए प्रदान की गई विभिन्न सेवाओं के लिए राज्य के सोनगढ़ तालुका की रामिलाबेन सिसिंग गामित को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। .

10वीं तक पढ़ने वाली रमीलाबेन ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत शौचालय निर्माण, बच्चों में कुपोषण उन्मूलन के साथ-साथ उनकी उन्नति के लिए अपनी कुशलता के माध्यम से जनजातीय समुदाय के सदस्यों के उत्थान और कल्याण के लिए आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया।

इस संबंध में प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पद्मश्री रमीलाबेन ने कहा, ठमैं राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मान के लिए धन्यवाद देती हूं।ठ वर्तमान सरकार ने आदिवासी समुदाय के सौना साथ और सौना विकास के मिशन को आगे बढ़ाते हुए उनके आर्थिक और सामाजिक विकास में तेजी लाने के लिए कई योजनाओं को लागू और कार्यान्वित किया है। मुझे खुशी है कि इन योजन